खण्ड-07 सत्र-05 अंक-60

बुधवार 28 फरवरी, 2024
09 फाल्गुन, 1945 (शक)

दिल्ली विधान सभा

की

कार्यवाही

सत्यमेव जयते

सातवीं विधान सभा

पाँचवां सत्र

अधिकृत विवरण

(खण्ड-07 सत्र-05 में अंक 50 से अंक 70 तक सम्मिलित हैं)

दिल्ली विधान सभा सचिवालय

पुराना सचिवालय, दिल्ली-110054

सम्पादक वर्ग

EDITORIAL BOARD

राज कुमार

सचिव

RAJ KUMAR

Secretary

महेन्द्र गुप्ता

उप-सचिव (सम्पादन)

MAHENDRA GUPTA

Deputy Secretary (Editing)

विषय सूची

सत्र-5 बुधवार, 28 फरवरी, 2024/09 फाल्गुन, 1945 (शक) अंक-60

क्र.सं.	विषय	पृष्ठ सं.
1.	सदन में उपस्थित सदस्यों की सूची	1-2
2.	विशेष उल्लेख (नियम-280)	3-38
3.	दिल्ली सरकार द्वारा प्रस्तावित सौर नीति को तथाकथित तौर पर रोके जाने के संबंध में सूचना एवं निंदा प्रस्ताव	39-42
5.	अल्पकालिक चर्चा (नियम-55)	43-91

दिल्ली विधान सभा

की

कार्यवाही

सत्र-5 बुधवार, 28 फरवरी, 2024/09 फाल्गुन, 1945 (शक) अंक-60

दिल्ली विधान सभा

निम्नलिखित सदस्य सदन में उपस्थित हुए:

1. श्री अजेश यादव
2. श्री अखिलेशपति त्रिपाठी
3. श्रीमती ए. धनवंती चंदीला ए.
4. श्री अजय दत्त
5. श्री अब्दुल रहमान
6. श्री बी. एस. जून
7. श्री दिनेश मोहनिया
8. श्री गिरीश सोनी
9. श्री हाजी युनूस
10. श्री जय भगवान
11. श्री जरनैल सिंह
12. श्री कुलदीप कुमार
13. श्री महेंद्र गोयल
14. श्री मुकेश अहलावत
15. श्री नरेश बाल्यान
16. श्रीमती प्रीति जितेंद्र तोमर
17. श्रीमती प्रमिला धीरज टोकस
18. श्री राजेश गुप्ता
19. श्री राजेन्द्र पाल गौतम
20. श्री शरद कुमार चौहान

21. श्री सोमदत्त
22. श्री शिवचरण गोयल
23. श्री सोमनाथ भारती
24. श्री सही राम
25. श्री एस. के. बग्गा
26. श्री महेन्द्र यादव
27. श्री मदन लाल
28. श्री नरेश यादव
29. श्री पवन शर्मा
30. श्री प्रलाद सिंह साहनी
31. श्री प्रवीण कुमार
32. श्री ऋतुराज गोविंद
33. श्री राजेष ऋषि
34. श्री संजीव झा
35. श्री विशेष रवि

दिल्ली विधान सभा

की

कार्यवाही

सत्र-5 बुधवार, 28 फरवरी, 2024/09 फाल्गुन, 1945 (शक) अंक-60

दिल्ली विधान सभा

सदन 11.22 बजे समवेत हुआ।

माननीया अध्यक्ष (श्रीमती राखी बिरला) पीठासीन हुईं।

माननीया अध्यक्षः सुरेंद्र कुमार जी, नियम 280 के तहत। (अनुपस्थित)। रामवीर सिंह बिधूड़ी जी।

विशेष उल्लेख (नियम-280)

श्री रामवीर सिंह बिधूड़ी (माननीय नेता, प्रतिपक्ष): आदरणीय सभापति महोदया, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी का ध्यान अरविंद केजरीवाल की सरकार की उस घोषणा की ओर दिलाना चाहता हूं जिसमें इसी हाउस में ये कहा गया कि एशिया की सबसे बड़ी गारमेंट की मार्किट गांधी नगर का कायाकल्प किया जाएगा। ये भी कहा गया कि दिल्ली की जो पांच और बड़ी मार्किटस हैं कमला नगर, लाजपत नगर, खारी बावली, कीर्ति नगर और सरोजनी नगर इनको रिडेवलेप किया जाएगा और इन मार्किटस के रिडेवलमेंट के लिए सौ

करोड़ रूपया का प्रावधान किया गया 2022-2023 के बजट में लेकिन मुझे बहुत खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि अभी तक गांधी नगर मार्किट का कायाकल्प करने का कार्य शुरू हुआ नहीं। इन पांच मार्किटस में रिडेवलेपमेंट का काम शुरू हुआ नहीं। सरकार ने ये कहा था कि हम इन मार्किटस में बिजली, पानी, सड़कों का सौंदर्यकरण, फायर आदि की बेहतरीन से बेहतरीन व्यवस्था करेंगे। आदरणीय उपाध्यक्ष महोदया आज इन मार्किटस में यदि आप जाएगें तो कूड़े के ढेर पड़े हुए हैं रिडेवलेपमेंट की बात छोड़ दीजिए, कायाकल्प की बात छोड़ दीजिए आप गांधी मार्किट में जाइए, आप कमला नगर मार्किट में जाइए, लाजपत नगर मार्किट में जाइए, खारी बावली में जाइए कूड़े के ढेर लगे हुए हैं सफाई की भी ठीक से व्यवस्था नहीं हो पा रही है। अब हमने ये फैसला किया कि हम इस मुददे को विधानसभा के अंदर उठाएं। सरकार की ओर से जो घोषणा की गई है या जो दिल्ली के लाखों व्यापारियों को जो सपने दिखाए गए हैं, घोषणा सच साबित हो, जो सपने दिखाए गए हैं वो सपने हमारे लाखों व्यापारियों के पूरे हों। तो मैं आपके माध्यम से एक बार फिर दिल्ली के लाखों व्यापारियों की ओर से मैं दिल्ली के माननीय मुख्यमंत्री महोदय से आग्रह करता हूं कि सरकार अपनी घोषणा के मुताबिक एशिया की सबसे बड़ी गारमेंट की मार्किट गांधी नगर का कायाकल्प करे और जो अन्य मार्किटस हैं जिनकी मैंने चर्चा की है जिनके उपर लगभग 100 करोड़ रूपया अरविंद केजरीवाल जी की सरकार को खर्च करना था, वह पैसा इन मार्किटस के रिडेवलेपमेंट के उपर खर्च होना चाहिए।

माननीया अध्यक्षः धन्यवाद।

श्री रामवीर सिंह बिधूड़ीः लाखों व्यापारियों को एक अच्छा संदेश इस हाउस के माध्यम से आज जाना चाहिए।

माननीया अध्यक्षः धन्यवाद।

श्री रामवीर सिंह बिधूड़ीः और मैं चाहूंगा कि सरकार इस पर।

माननीया अध्यक्षः हो गया इतना ही लिख के दिया है।

श्री रामवीर सिंह बिधूड़ीः अगर कुछ जानकारी अगर सभी विधायकों को उपलब्ध करा दें तो मैं समझता हूं कि मैं बहुत आभारी रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अध्यक्ष महोदया।

माननीया अध्यक्षः सोम दत्त।

श्री सोम दत्तः धन्यवाद अध्यक्ष जी, अध्यक्ष जी मैं आपका ध्यान आशा वर्करों की ओर दिलाना चाहता हूं और मेरी असेंबली में भी लास्ट वीक भी आशा वर्करों की डेलीगेशन आई थी। आशा वर्कर हमारे हेल्थ सिस्टम में बड़ा इम्पोरटेंट रोल प्ले करती हैं और फ्रंट लाइन वर्कर का काम करती हैं। लगभग हर मौहल्ले, हर गली और हर घर तक आशा वर्कर का जाना होता है और बर्थ से लेकर डेथ तक का सारा ब्यौरा भी यही रखती हैं। जच्चा बच्चा और सीनियर सीटिजन इनकी हेल्थ सिस्टम के अंदर पूरा इनका तमाम व्यवस्थाएं अरेंजमेंटस कराना इनका इंपोरटेंट रोल होता है और कोविड पीरियड के दौरान भी जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को टच करने से इनफैक्शन की वजह से डर की

वजह से एक दूसरे की मदद नहीं कर रहा था उस दौरान में भी इन आशा वर्करों ने घर घर जाकर ऑक्सीमीटर, आक्सीजन लेवल चैक करना और तमाम सुविधाएं जो भी अवेलेबल थीं वो सारी घर घर तक मुहैया कराई और इसके अलावा तमाम जगह पे मैडिकल फैसेलिटीज भी अवेलेबल कराने में इनका बड़ा इंपोरटेंट रोल है लेकिन आशा वर्करों को कई बेसिक फेसेलटीज नहीं है। ना तो इनकी कोई मिनीमम वेज है, ना इनको कोई मैडिकल फैसेलिटी पर्सनली अपने या परिवार के लिए मिलती है, ना रिटायरमेंट के बाद किसी तरह का कोई बेनिफिट होता और ये तमाम इशूज को लेकर आशा वर्कर मेरे पास आफिस में मिलने डेलीगेशन आई थी। मेरी आपसे रिकवेस्ट है कि आशा वर्कर जो इतना इंपोरटेंट रोल हमारे हेल्थ सिस्टम में प्ले करती हैं इनके लिए कुछ सोचा जाए। कोई मिनिमम वेज का कुछ ऐसा प्रावधान किया जाए जिससे इनका भी परिवार है। सारी सुविधाएं इन तक भी पहुंचे, बेसिक फेसीलिटी जो ये दूसरों तक पहुंचाना चाहती हैं, कम से कम इनको और इनके परिवारों को भी वो फैसेलिटीज मिलनी चाहिए, चाहे वो फाइनेंनशियल बेनिफिटस हैं, चाहे वो मैडिकल बेनिफिटस हैं और आपने अपनी बात रखने का मुझे मौका दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।

माननीया अध्यक्षः अजय दत्त जी।

श्री अजय दत्तः अध्यक्षा जी सबसे पहले तो आपको इस सीट पर बैठे हुए मुझे बड़ा गर्व हो रह है और आपने जब भी सदन की बैठक की अध्यक्षता की है बहुत अच्छे रूप से चली है। मैं आपका धन्यवाद देना चाहता हूं आपने मुझे मेरे क्षेत्र के मुददे पर 280 में बोलने

का मौका दिया। अध्यक्ष जी दिल्ली के अंदर कई लाख कैमरे लगाए गए और ये माननीय मंख्यमंत्री जी का सपना था कि दिल्ली के अंदर कई लाख कैमरे लगें और दिल्ली को सुरक्षित बनाया जाए। महिलाओं की सुरक्षा की जाए और जितने भी वारदात दिल्ली के अंदर होती हैं उसको रोका जाए, वो कैमरे में आए और उसके बाद हमने ये देखा पिछले कई सालों में कि आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल जी द्वारा जो भी कैमरे लगाए गए उनसे बहुत सारे केस सुलझे, पुलिस को बहुत मदद मिली। अध्यक्ष जी मैं अपने क्षेत्र में लगाए गए कैमरों पे और जो कैमरे नहीं लगे हैं जो बच गए हैं उन पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। अंबेडकर नगर में करीबन एक फेज में सोलह सौ कैमरे लगे और बाकी कैमरे पैण्डिंग हैं। सैकिण्ड फेज के कैमरे लगने शुरू हुए उसमें भी करीबन छह सौ कैमरे पैण्डिंग हैं और जो ऐजेंसी फर्स्ट फेज के कैमरे लगा रही थी उसका कुछ अता पता नहीं है। जो जिस ऐजेंसी ने फर्स्ट फेज के कैमरे लगाए उसने उसकी मेंटेनेंस करनी बंद कर दी है। तो बहुत सारी जगह कैमरे बंद हैं। मेरा एरिया एक ऐसा है जहां बहुत डैंस पोपुलेशन है और आए दिन अखबारों में चोरी और कई सारी क्षेत्र में जो वारदातें होती हैं उसमें नाम आता है। पहले ये सब रूक गए थे क्योंकि एविडेंस मिल जाता था लेकिन कैमरे ना चलने की वजह से बहुत सारी जगह बाइक चोरी हो रही है, बैट्रीयां चोरी हो रही हैं और लोग मुझे आकर कहते हैं भई आप अपने कैमरे की फुटेज दिखाओ। जब देखने जाते हैं तो कैमरे बंद पाए जाते हैं। दूसरे फेज में जब कैमरे लगाए उसमें भी करीबन 600 के आसपास कैमरे नहीं लगे हैं

और मैंने पीडब्लयूडी को इसके बारे में लिखित में भी दिया, मैंने हमारी पीडब्लयूडी मिनिस्टर को भी इसके बारे में लिखित में दिया। मीटिंगें हुई, पीडब्लयूडी मिनिस्टर आतिशी जी ने इस पर संज्ञान भी लिया उन्होंने आर्डर भी किए कि ये जितनी भी पुराने कैमरे उसकी मैंटेंनेंस हो और जो नए कैमरे हों वो जल्दी से लगें तो जो नई ऐजेंसी आई है उसने भी अब काम करना बंद कर दिया है और जिसकी वजह से लोग परेशान हैं। आए दिन समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। अध्यक्षा जी मेरा आपसे निवेदन हैं कि पीडब्ल्यूडी को आप आदेश दें कि जितने भी कैमरे लगे हैं एक तो उनकी मेंटेंनेंस हो और जो बाकी कैमर बच गए हैं उनको लगाया जाए और एक और इशू जो देखने में आया है वो ये है कि जितने नए कैमरे लगे हैं वो अलग अलग लोगों के घर से मीटर से जोड़े गए हैं जिसमें सबसीडी देनी बाकी है वो भी नहीं मिल रही है जिसकी वजह से बहुत सारे लोग उन कैमरों को विदड्रा करना चाहते हैं क्योंकि उनके बिजली के बिल बढ़ रहे हैं।

माननीया अध्यक्षः बहुत बहुत धन्यवाद।

श्री अजय दत्तः तो मेरा आपसे अनुरोध है कि आप इन तीनों चीजों पे संज्ञान लें और पीडब्लयूडी के अधिकारियों को आप दिशा निर्देश दें। अध्यक्षा जी आपने मुझे बोलने का मौका दिया धन्यवाद।

माननीया अध्यक्षः जरनैल सिंह जी।

श्री जरनैल सिंहः थैंक्यू स्पीकर साहिबा, स्पीकर साहिबा मैं एक बहुत ही गंभीर मामला अपनी विधान सभा का आपके सामने रखने जा

रहा हूं। पंजाबी में एक कहावत है 'सड़ ना रीस कर' ये कहावत उन लोगों के लिए कही गई है जो दूसरे के काम को देख कर ईर्ष्या करते हैं और उनको कहा गया है कि आप भी कंपीटीशन करो आप बराबरी करो, आप जलो मत। मेरे क्षेत्र में विकास कुंज नाम की एक सोसाइटी है, इस सोसाइटी में मैंने साल 2020 के अंदर लगभग चार साल पहले आज से एक बेडमींटन कोर्ट बनवाया, दिल्ली सरकार की तरफ से बनवाया। प्रोपर टैण्डर होकर वो बेडमींटन कोर्ट बना और वहां बेडमींटन कोर्ट बनने के बाद उस कालोनी वालों में इतनी खुशी थी कि लगातार मैं भी वहां जाता रहा और वहां पर लोग बेडमींटन खेलते रहे। छोटे बच्चों से लेकर, बड़ों से लेकर बुजुर्ग तक सब खेल रहे थे। अब जैसे ही 2024 शुरू हुआ लगभग एक हफ्ता पहले डीडीए द्वारा ये नोटिस दिया जाता है मतलब पब्लिक के पैसे से पब्लिक लैंड के उपर, पब्लिक के फायदे के लिए कोई सर्विस हमने दी है, कोई सुविधा दी है और डीडीए को परेशानी हो रही है। अब डीडीए कौन संभालता है। डीडीए किसके कहने पर ये नोटिस देता है ये किसी से छुपी बात नहीं है। मैं फिर भी बता दूं वहां के निगम पार्षद भाजपा से हैं और वहां के सांसद भी भाजपा से हैं जिनके कहने पर ये नोटिस दिया गया है। अब ये नोटिस 17 फरवरी 2024 को इशू होता है और उसके लगभग एक हफ्ते बाद उस बेडमींटन कोर्ट को जो कि सरकारी पैसे से बना है उसको तहस नहस कर दिया जाता है, बुलडोजर से उसको आकर पूरी तरह तबाह कर दिया जाता है। इस चीज को लेकर वहां के लोगों में बहुत रोष है। अब होना तो ये चाहिए था भई केजरीवाल सरकार

कुछ काम करा रही है तो इनको भी उससे सीखना चाहिए था, ये भी करवाते वहां पर ऐसे काम। उस कालोनी में हमने सड़कें बनवाई है, उस कालोनी में हमने बाउंड्री वॉल बनवाई है, उस कालोनी में हमने सीसीटीवी कैमरे लगवाए हैं, उस कालोनी में हमने ऑटोमैटिक boom barrier लगवाए हैं, वहां पर बाउंड्री वॉल के उपर fencing करवाई है, कैमरे लगवाएं हैं, लाइटें लगवाई हैं बेहिसाब काम करवाएं हैं तो अब इन्होंने एक बहाना दे दिया भई इस चीज के लिए आपने कोई एनओसी नहीं ली थी। ऐसे तो अब सड़कें भी तुड़वा दी जाएगीं, कैमरे भी हटवा दिए जाएंगे तो ऐसे लोगों के उपर डीडीए कुछ मतलब डीडीए को हम यहां से हम कोई ऐसी डायरेक्शनस दें कि जो काम पब्लिक के लिए हो रहे हैं मतलब झुग्गी बन जाती है या कुछ अलग तरीके के इनक्रोचमेंटस हो जाती हैं वहां पर डीडीए नहीं जाता। अलग अलग तरीके के कई बारी किसी को फायदा पहुंचाने के लिए इनक्रोचमेंटस हो जाती हैं वहां डीडीए सालों साल नहीं जा रहा और जो चीज पब्लिक के फायदे के लिए बन रही है वहां पर डीडीए इतनी सख्त कार्रवाई कर रहा है। तो ये जो बीजेपी वालों की बुद्धि भ्रष्ट हुई पड़ी है और इस तरीके के काम करवा रहे हैं मेरे को लगता है जो वहां की जनता इस समय पूरी रोष में है। मेरे को छोटे बच्चे मिले, बड़े लोग मिले हर आदमी पूरे रोष में था और मेरे को लगता है आने वाले समय में बहुत जल्दी ऐसे तानाशाही सोच वाले, ऐसे घटिया सोच वाले लोगों को जनता सबक जरूर सिखाएगी। इस सदन में ये मामला उठाने से मेरा सिर्फ ये मकसद था कि इस पर कोई कार्रवाई की जाए स्पीकर साहिबा ऐसी

कोई डायरेक्शनस यहां से इशू की जाएं ताकि पब्लिक के पैसे का इस तरीके से जो है मतलब निरादर ना हो। उस प्रापर्टी को ऐसे खराब ना किया जाए। थैंक्यू स्पीकर साहिबा।

माननीया अध्यक्षः हाजी युनूस जी।

श्री हाजी युनूसः धन्यवाद अध्यक्षा महोदय, आपने मुझे मेरी विधानसभा के इतने महत्वपूर्ण मुददे पर बोलने का मौका दिया। अध्यक्षा महोदय, मेरी विधानसभा में दिल्ली सरकार की एक डिसपैंसरी थी जो मैंने पहले भी सदन में एक दो बारी इस मुददे को उठाया है। उस डिसपैंसरी को पौली क्लिनिक में तबदील कर दिया गया है। पौली क्लिनिक में पास करा गया कि इसका रेनोवेट करके इसको पौली क्लिनिक बनाया जाए क्योंकि मेरी विधानसभा और आसपास की विधानसभाओं में स्वास्थ्य सुविधाओं का बहुत बुरा हाल है। कोई भी स्वास्थ्य सुविधाएं वहां आसपास कोई हास्पिटल नहीं है तो इस डिसपैंसरी का टैण्डर हो गया। टैंडर के बाद जब ठेकेदार ने काम शुरू करा तो पाया कि बिल्डिंग की हालत बहुत खस्ता है तो उन्होंने इसके लिए एक जांच के आदेश कर दिए। वो जांच इतनी लंबी चली थर्ड पार्टी जांच के आदेश हो गए, फ्ल्ड विभाग द्वारा ये डिसपैंसरी बनाई गई। फ्ल्ड डिपार्टमेंट ने वो जांच को इतना लंबा डाल दिया, इतना लंबा डाल दिया कि वो जांच बहुत टाइम के बाद तो वो जांच होकर रिपोर्ट आई। रिपोर्ट आने के बाद भी दो साल कोरोना काल में गुजर गए। कोरोना काल के बाद फिर दो साल गुजर चुके हैं लेकिन इसका काम आज तक दोबारा शुरू नहीं हुआ और ये खण्डहर बनी पड़ी है और मेरा आपके माध्यम

से यही अनुरोध है जिस तरह से आम आदमी पार्टी सरकार अरविंद केजरीवाल जी की सरकार स्वास्थ्य में, शिक्षा में इतने बेहतरीन काम कर रही है। दिल्ली सरकार बनाना चाहती है लेकिन अधिकारी, कौन अधिकारी ऐसे हैं जो इसको रोकने पर लगे हुए हैं। तो मेरी आपके माध्यम से ये दरखास्त है ये अनुरोध है कि इसको जल्द से जल्द उन अधिकारियों को आदेश दिया जाए और मंत्री जी के द्वारा मैंने सत्येन्द्र जैन जी को भी पहले कई लैटर दिए थे और अब जो मौजूदा स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज जी को भी मैं लैटर दे चुका हूं लेकिन इस पर कोई अमल नहीं हो पा रहा है। तो मेरी आपके माध्यम से गुजारिश है कि इस डिसपेंसरी को जल्द से जल्द बना दिया जाए जिससे वहां की जनता को इसका लाभ मिल सके। धन्यवाद अध्यक्षा महोदया।

माननीया अध्यक्षः विशेष रवि जी।

श्री विशेष रविः बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। मैं आज दिल्ली के जो सिविल डिफेंस वॉलेंटियर्स हैं उनका जो मुददा है उसके बारे में सदन को अवगत कराना चाहता हूं। मैडम वैसे तो आज हाउस के अंदर चर्चा भी लगी हुई है लेकिन ये कल मैंने 280 में लगाया था तो वो आ गया है तो मैं अपनी बात रख रहा हूं उसके उपर। दिल्ली के अंदर लगभग दस हजार सिविल डिफेंस वॉलेंटियर्स हैं जो पिछले चार महीने से, पिछले चार महीने से लगातार जो है वो अपनी मांग को ले के जो हैं प्रोटेस्ट पर बैठे हुए हैं। ये 01-11-2023 से ये लोग जो हैं लगातार जो है धरने पे बैठे हुए हैं। इन सब को जो है चार महीने पहले अचानक जो है बिना किसी नोटिस के, बिना किसी जानकारी के जो है

निकाल दिया गया और तब से ये लोग धरने पे बैठे हुए हैं। सिविल डिफेंस वॉलेंटियर्स मैडम वो लोग हैं जो इस समय दिल्ली सरकार के अंदर चालीस लगभग ऐसे विभाग हैं जिसके अंदर वो अपनी सेवाएं दे रहे थे। वो पीछे स्टाफ में बैठ के काम करते थे, विंडो पे कहीं पे काम करते थे, कहीं पे एसडीएम को असिस्ट कर रहे थे, कहीं पर जो है जो फूड एंड सप्लाई डिपार्टमेंट है हमारा वहां पर जो है अपनी सेवाएं दे रहे थे और इन्होंने सिविल डिफेंस वॉलेंटियर्स ने जो है जब कोरोना आया तो उस समय जो है फ्रंट लाइन कोरोना वारियर्स के रूप में भी काम किया। दिल्ली सरकार की जितनी भी बड़ी बड़ी योजनाएं थी जैसे रेड लाइट ओन, गाड़ी ऑफ जैसी योजनाएं थीं, अन्य जितनी भी योजनाएं थी, हर जगह जो है इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं लेकिन ये अभी पिछले चार महीने से बहुत परेशान हैं, बहुत दुखी हैं। सिविल डिफेंस वॉलेंटियर्स जो हैं वो सिविल डिफेंस एक्ट 1968 में इनका गठन हुआ तब से ही जो है अलग अलग सेवाएं ये अपनी दे रहे हैं और समय समय पे जो है संशोधन करके इस एक्ट में जो है इनकी सेवाओं को जो है जोड़ा गया। डिजास्टर मैनेजमेंट के अंदर भी जो है इनको लाया गया है, वहां भी इनकी सेवाएं ली जा रही हैं। तो इस समय ये सभी वर्कर जो हैं बहुत परेशान हैं, बहुत दुखी हैं। महीनों से इनके घर में राशन की, बच्चों की फीस की अन्य सेवाएं जो हैं वो नहीं इनको मिल पा रही हैं, जैसा मैंने कहा कि आज सरकार जो है इस पे सरकार के द्वारा यहां पर विधानसभा के अंदर जो है चर्चा भी की जा रही है और मुझे विश्वास है कि दिल्ली सरकार जो है इनकी समस्याओं को लेकर बहुत गंभीर है और आज की चर्चा और कल की चर्चा के बाद

एक प्रस्ताव जो है वो जल्द ही एलजी महोदय के पास चला जाएगा जिससे इनकी समस्यओं का जो है हल हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपने बोलने का मौका दिया।

माननीया अध्यक्ष: राजेश ऋषि जी।

श्री राजेश ऋषि: धन्यवाद अध्यक्षा महोदया जो आपने 280 में मुझे अपने क्षेत्र की समस्या को रखने के लिए मौका दिया। आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे नेता अरविंद केजरीवाल जी ने अच्छे स्वास्थ्य का जो सपना देखा था वो दिल्ली के जनकपुरी सुपर स्पेशली हास्पिटल में पूरा हुआ। हमारी जनकपुरी की जनता के लिए ये बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही बढ़िया हास्पिटल है। हमारे सत्येन्द्र जैन जी जो उस समय स्वास्थ्य मंत्री थे उन्होंने इसका शुभारंभ किया। इसमें वर्ल्ड क्लास cath lab लगी हुई है जो heart के इलाज के लिए काम में आती है। यहां पर सात नए ओपरेशन थियेटर बने हैं जो इतने खूबसूरत और वर्ल्ड क्लास हैं इसमें instruments बहुत बढ़िया लगे हुए हैं। साथ ही साथ इसमें सीसी यूनिटस बनी हैं दस दस बैड की। इसके अंदर brain, heart, किडनी, लीवर इन चार चीजों का इलाज होता है। यहां एमआरआई भी लगी है जो मुफ्त में होता है यहां CAT scan भी मुफ्त में होता है यहां सारी दवाइयां मुफ्त में मिलती हैं और इसके साथ ही एक कैंसर institute है। ये कैंसर institute दिलशाद गार्डन में जो हमारा दिल्ली कैंसर institute है उसकी एक ब्रांच है लेकिन प्राबलम सबसे बड़ी क्या है हमारा जो जनकपुरी super speciality हास्पिटल के अंदर बना हुआ जो दिल्ली कैंसर institute है इसमें दस कीमो थैरेपी के बैड

लगे हुए हैं। इसमें केवल ओपीडी चलती है लेकिन आज हालात ये हो गए हैं कि यहां पर डाक्टर्स नहीं हैं। डाक्टर्स हैं तो केवल जेआर हैं। जेआर कुछ नए आते हैं फिर ट्रांसफर हो जाते हैं फिर नए आते हैं क्योंकि संचालन जो दिलशाद गार्डन से हो रहा है वो हो नहीं पा रहा। ना वहां से कोई सीनियर डाक्टर देखने आता है, ना वहां के डायरैक्टर वहां पे कभी आते हैं। कई बार मैं बुलाता हूं आएंगे, एक एक महीने के बाद टाइम देगें उसके बाद भी पता चलता है कि कुछ नहीं करते वो। एक जमाना था यहां पर डायरैक्टर थे राजेश ग्रोवर जिन्होंने दिलशाद गार्डन में जो दिल्ली कैंसर institute और जनकपुरी जो कैंसर institute है इसको बहुत ही खूबसूरत तरीके से चलाया, हर इलाज हो जाते थे उनको फोन करो सारे काम होते थे उन्होंने तो ब्लड कैंसर का इलाज करने के लिए भी सारी तैयारी कर ली थी लेकिन उस समय के चीफ सैक्रेट्री और एलजी साहब ने उनसे जबर्दस्ती रिजाइन ले लिया। उसके बाद से इस हास्पिटल की स्थिति बिगड़ती चली गई, बिगड़ती चली गई। मेरे इस दिल्ली कैंसर institute के अंदर एक करोड़ों रूपये की मशीन लगी हुई है linear accelerator जिसको एक bunker बनाने के लिए भाभा atomic सैंटर से इंजीनियर्स आए थे जिन्होंने बनाया और उसके अंदर उस मशीन को लगाया गया लेंकिन ये मशीन लगभग छह सात साल से बंद पड़ी है। इसके अंदर डाक्टर्स नहीं हैं। मैंने अपने नेता मनीष सिसौदिया जी जो स्वास्थ्य मंत्री थे उनको मैंने लैटर दिया कि ये दिलशाद गार्डन से चल नहीं पा रही क्यों ना इसे हमारे जनकपुरी Super Speciality हास्पिटल के हैंड ओवर कर दिया जाए। हमारे यहां

डाक्टर्स तैयार थे वो बोले कि हमारे पास न्यूकलियर डाक्टर्स हैं जो इन मशीनों को चला सकते हैं जबकि दिल्ली कैंसर इंस्टिटयूट के पास ऐसे डॉक्टर नहीं हैं तो इसीलिए इसको ट्रांसफर के लिए दिया, मनीष जी ने इसके ऊपर कार्रवाई शुरू की, उसके बाद ये कार्रवाई चलते–चलते आज एक साल से ऊपर हो गया, ये आज तक ट्रांसफर नहीं हो पाई जबकि डॉक्यूमेंट्स बन गए, सब कुछ हो गया लेकिन अभी तक उन्होंने इनको ट्रांसफर नहीं किया, जिसके कारण आज न तो वहां डॉक्टर्स हैं, न वो डॉक्टर्स भेज रहे हैं, न ट्रांसफर कर रहे हैं। मेरा आपके माध्यम से ये अनुरोध है कि स्वास्थ्य मंत्री जी बैठे थे, वो भी वहां पर आए थे, उन्होंने भी देखा कि इतना शानदार हॉस्पिटल है, इतनी बढ़िया तरीके से मैनेजमेंट हो रहा है, बढ़िया तरीके से चल रहा है, सारी दवाइयों के लिए शानदार लाइनें लगी हुई हैं। उनको मैं ऑपरेशन थियेटर दिखाकर लाया कि देखो ये ऑपरेशन थियेटर्स बनकर तैयार हैं, हैंडओवर इसलिए नहीं ले रहे क्योंकि यहां पर कोई एक ऐसा पेच फंस गया है कि जिसमें आप सर्जरी के डॉक्टर्स नहीं रख सकते। जब सर्जरी के डॉक्टर नहीं होंगे तो वो हॉस्पिटल चलेगा कैसे? मेरा ये ही आपसे कहना है कि आपके माध्यम से ये दिल्ली कैंसर इंस्टिटयूट जो है उसको जनकपुरी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल को ट्रांसफर कराया जाए और कैंसर हॉस्पिटल जब ट्रांसफर हो जाएगा, हमें पूरी उम्मीद है कि हमारी जो linear accelerator करोड़ों रुपये की मशीन पड़ी है, ये हमारे न्यूक्लियर्स डॉक्टर्स जो हैं दिल्ली जनकपुरी के वो इसको चला लेंगे और जनता के लिए जो लगाया गया इतना बड़ा पैसा है वो किसी के काम आयेगा।

मेरे को आपने बोलने का मौका दिया आपको बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत-बहुत धन्यवाद।

माननीया अध्यक्षः संजीव झा जी।

श्री संजीव झाः बहुत-बहुत धन्यवाद अध्यक्ष महोदय कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। मैडम मैं अपने विधान सभा का जो अनऑथराइज्ड कॉलोनी है मैं उसकी तरफ आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी का ध्यानाकर्षण चाहता हूं। अनऑथराइज्ड कॉलोनी में 2007 के नक्शे में जो कॉलोनियां हैं उसमें तो डेवलपमेंट हो पाता है, उसके बाद की जो कॉलोनी सैंक्शन हुई उस पर कोई काम नहीं हो पाता है। उसका कारण ये है कि चूंकि 2007 का जो नक्शा था उसके बाद जितने भी एक्सटेंड हुए उसका कभी, उसको ऐड नहीं किया गया। कई बार हम लोग एमएलए फंड से वो काम करा देते थे। लेकिन अब जैसे सदन में पिछली बार भी चर्चा हुई कि अब वहां भी काम करने के लिए कहा लैंड ओनिंग एजेंसी का एनओसी चाहिए। अब चूंकि वो अनऑथराइज्ड कॉलोनी है तो वहां पर लैंड ओनिंग एजेंसी तो यूडी ही होना चाहिए। अब उसमें कह दिया है डीडीए का एनओसी दो, अब वो डीडीए के पास कोई procedure ही नहीं है वहां के एनओसी देने का। अब उसका नुकसान ये हो रहा है कि उस एरिये में डेवलपमेंट जो हमारा है, एमएलए फंड हम लगा नहीं पा रहे हैं। और बहुत सारी ऐसी कॉलोनियां हैं, मेरे यहां ऐसी 42 कॉलोनियां जो एक्सटेंड हो चुका है। एक तो सॉल्यूशन इसका ये है कि केंद्र सरकार जैसे 2007 में एक टाइमलाइन देकर के आरडब्लूए को कहा था कि इनका सब्मिट करो

ताकि उसमें लीगली हम विकास कर पाए। और जब तक ये नहीं होता कम से कम एमएलए फंड जो हम लोग लगा रहे थे, एमएलए फंड लगाने दिया जाए, अन्यथा बारिश के मौसम में वहां के लोगों का निकलना दूभर हो जाता है। तो हम चाहकर के भी आज, हमने, 20-22 फाइल हमारा अनऑथराइज्ड कॉलोनी में, ऐसी कॉलोनियों में सड़कों के लिए दिया था लेकिन सारा वापस आ गया। तो मैं आपके माध्यम से यही निवेदन करना चाहता हूं कि ये जो एनओसी की बात कर रही है यूडी, ये ठीक नहीं है, पहले ऐसा नहीं था, ये अभी 6 महीने से ऐसा होने लगा है। तो इसको हटा दिया जाए ताकि हम कम से कम एमएलए फंड वहां लगा पाए और वो तमाम हमारे विधान सभा की कॉलोनियां जहां सड़कों की जरूरत है वो सड़क बन पाए। धन्यवाद।

माननीया अध्यक्षः प्रवीण कुमार जी।

श्री प्रवीण कुमारः माननीया अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद। अध्यक्ष जी, बहुत पहले एक कुछ भजन आया था जिसमें चार लाइनें ये थी कि-

'भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना,

पुष्प नहीं बन सकते तो तुम कांटे बनकर मत रहना।'

लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने सिविल डिफेंस के वॉलन्टियर्स के लिए और बस मार्शल्स के लिए कांटे बनने का काम किया है अध्यक्ष जी। अध्यक्ष जी, एक तरफ तो दिल्ली के मुख्यमंत्री- अरविंद केजरीवाल जी की सरकार द्वारा सिविल डिफेंस वॉलन्टियर्स को बस मार्शल्स की

जॉब दी जाती है, अलग-अलग विभागों में जॉब दी जाती है और उनकी लगातार तनख्वाह भी आती है, लगातार सुचारू रूप से सही चलता है लेकिन भारतीय जनता पार्टी को वो गवारा नहीं हुआ और भारतीय जनता पार्टी ने सिविल डिफेंस वॉलन्टियर्स को, बस मार्शल्स को नौकरी से हटा दिया एल.जी. के माध्यम से। ये बहुत ही दुख की बात है अध्यक्ष जी और कल, मैं सिविल डिफेंस वॉलन्टियर्स से कल भी मिला था और परसों भी मिला था। और क्योंकि कई सारे सिविल डिफेंस वॉलन्टियर्स मेरे क्षेत्र में भी रहते हैं, बेचारे बहुत ज्यादा दुखी हैं और ये उनकी युवा अवस्था है जब उनका स्ट्रेगलिंग टाइम है और परिवार में समझ लीजिए एक ही व्यक्ति है जो कमाने वाला है और पिछले 4-5 महीने से वो बेरोजगार बैठा है, न उसकी तनख्वाह आ रही है, न उसके घर में राशन है, मतलब कई सारे सिविल डिफेंस वॉलन्टियर कहते हैं कि सर हम आत्महत्या करने को भी इस समय जो है मजबूर हैं, इस-इस तरीके की बातें जो हैं इस समय करते, इतने दुखी हैं वो। एक सिविल डिफेंस वॉलन्टियर को जो जानता हूं, राजेश नाम है उसका, वो पिछले 20 साल से सिविल डिफेंस में है और उसको एकाएक जो है उसको हटा दिया गया, 20 साल नौकरी करने के बाद जब उसकी ऐज जो है 50 के आसपास पहुंच चुकी है। अब वो उसे कहां नौकरी मिलेगी। तो इस तरीके का रवैया जो है वो भारतीय जनता पार्टी द्वारा जो है दिल्ली के लोगों से दुश्मनी निकालने के लिए लगातार किया जा रहा है। और आज मैं इस सदन पटल के माध्यम से ये धन्यवाद करना चाहूंगा अरविंद केजरीवाल जी की सरकार का कि कल उन्हें बोलकर भी आया था मैं

कि हम जो है दिल्ली विधान सभा में आपकी चर्चा करेंगे और आज धन्यवाद करना चाहता हूं इस सदन का भी और अरविंद केजरीवाल जी का भी कि इस इशू को जो है नियम 55 के अंतर्गत जो है उन्होंने अल्पकालिक चर्चा में यहां पर सदन में रखा आज, जो इसमें बिजनेस में लगा हुआ है और उन्होंने एक आश्वासन मुझे दिया कि आप जो है इसे सदन से पास कर दीजिए बाकि भारतीय जनता पार्टी से हम निपट लेंगे और भारतीय जनता पार्टी अगर नहीं समझ में आता है इनको, भारतीय जनता पार्टी अगर इनको हमारी बात समझ में नहीं आती तो इस समय जो है जो जनरल इलेक्शन में सातों की सातों सीटों में जमानत जब्त कराने का काम जो है वो सिविल डिफेंस वॉलन्टियर करेंगे भारतीय जनता पार्टी की।

माननीया अध्यक्षः मुकेश अहलावत जी।

श्री मुकेश अहलावतः अध्यक्ष महोदया, आपने मुझे 280 में बोलने का मौका दिया आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। अध्यक्ष महोदया, मेरी विधान सभा में एक छोटी सी कॉलोनी है Indira Jheel नाम की, उसमें, पहले वो 8-9 फुट नीचे थी तो उसका, न उधर सीवर था, न पानी था और न उधर नालियां थी लेकिन सत्येन्द्र जैन जी जो हमारे पूर्व मंत्री रहे हैं उनके सहयोग से उधर पानी, सीवर सब डल गया है। लेकिन अब वो उसका लेवल काफी नीचे था तो ऊपर हो गया तो उधर जो पोल थे इलेक्ट्रिक पोल थे वो सारे के सारे नीचे आ गए। अब मैं कई बार बोल चुका टीपीडीएल वालों को कि एक बार आप वहां पर विजिट करें, देखें। वो केवल 7-8 फिट के दायरे में आ गया है और

यदि उसको हटाया नहीं जाएगा तो वहां पर कोई भी दुर्घटना घट सकती है। तो मेरा आपसे आग्रह है कि आप एक बार वो टीपीडीएल वालों को बोला जाए और वो वहां पर आएं। धन्यवाद।

माननीया अध्यक्षः भूपेन्द्र सिंह जून जी।

श्री बी. एस. जूनः स्पीकर मैडम, मैडम संभालका गांव में दो गवर्मेंट स्कूल्स हैं और उनमें 4 शिफ्ट लगती हैं। बच्चों की टोटल स्ट्रेंथ होगी तकरीबन 15 हजार। स्कूल आने जाने के लिए बच्चों को कापसहेड़ा, बिजवासन, जो बिजी रोड है उसको क्रास करना पड़ता है कापसहेड़ा साइड से स्कूल की तरफ। हर आए दिन कभी न कभी कोई न कोई एक्सीडेंट या तो किसी स्टूडेंट का या किसी टीचर का या किसी स्टाफ का होता रहता है। वहां पर न तो कोई जेबरा क्रॉसिंग है, न कोई ट्रैफिक लाइट है, न कोई फुटओवर ब्रिज है और न कोई अंडरपास या सबवे है। मैंने ये कई बार शिक्षा मंत्री के सामने भी मसला उठाया, उनका एटिटयूड पॉजिटिव था कि हां वो प्रॉब्लम है। पीडब्लूडी वालों ने ऑब्जेक्शन किया क्योंकि स्पेस कम है इसलिए फुटओवर ब्रिज नहीं बन सकता। तो मैंने उनको एक सुझाव दिया कि आप एक साइड शुरू कीजिए, सड़क क्रास कीजिए और फुटओवर ब्रिज को स्कूल प्रेमिसेस में ड्राप कर दीजिए ताकि बच्चों को वो सड़क क्रास करनी न पड़े और फुटओवर ब्रिज से, लड़कियों का भी स्कूल है और लड़कों का भी स्कूल है, उस फुटओवर ब्रिज से वो स्कूल में आ-जा सके। तो अभी तक इस पर कोई कार्रवाई हुई नहीं, डेली एक्सीडेंट हो रहे हैं। मेरी आपके माध्यम से यही रिक्वेस्ट है कि एजुकेशन डिपार्टमेंट इसके बारे में

सोचे और बहुत इम्पोर्टेंट इशू है कि वहां एक फुटओवर ब्रिज बनाए और उसको ड्राप कर दे स्कूल में, उससे कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपने समय दिया उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

माननीया अध्यक्षः धन्यवाद जी। जी, मंत्री जी।

माननीय परिवहन मंत्री (श्री कैलाश गहलोत): मैं थोड़ा इस पर आज, अगर एलाऊ करें तो मैं,

माननीया अध्यक्षः जी-जी बिल्कुल। जवाब दे रहे हैं मंत्री जी, सुनिये जून साहब।

माननीय परिवहन मंत्रीः तो इसमें शिक्षा विभाग का तो कंसर्न है ही, मैं सभी माननीय विधायक को ये भी बताना चाहूंगा कि ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में एक पूरा vertical है उसको रोड सेफ्टी के नाम से जाना जाता है। तो रोड सेफ्टी सेल को भी अगर आप ये विषय के बारे में लिखते हैं तो रोड सेफ्टी चूंकि उसमें एक स्पेशल कमिश्नर ऑलरेडी अपॉइंटेड है जिसका ये डयूटी है कि अगर इस तरह के जितने भी इशू सामने आते हैं तो वो उसको एग्जामीन करें और कुछ दिन पहले हमने काफी सारे जो, जहां पर स्कूल्स का एक ये कलस्टर्स हैं, जहां पर काफी हजारों की संख्या में अगर बच्चे आते हैं तो किस तरीके से बच्चे जो हैं वो रोड को, रोड से स्कूल को एक्सेस बिना किसी परेशानी के, बिना किसी एक्सीडेंट्स के एक्सेस कर सकें, इसमें हमने आईआईटी-डेली को भी rope in किया है और काफी और जो एनजीओस हैं उनको भी हमने rope in किया। तो मेरा अनुरोध ये ही है कि अगर

किसी माननीय विधायक का ये कंसर्न है कि बच्चों को रोड क्रास करने में दिक्कत हो रही है, स्कूल तक पहुंचने में दिक्कत हो रही है या वो अपने आपको एक्सीडेंट के लिए एक्सपोज कर रहे हैं तो फिर उसको ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को भी लिखें ताकि ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट और जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है, दोनों मिलकर इसका कोई न कोई सॉल्यूशन निकाले।

माननीया अध्यक्षः समझ आ गया आपको। महेंद्र गोयल जी आपका विषय लगा है, बोलना चाहेंगे।

श्री महेंद्र गोयलः इजाजत हो तो बोल देंगे।

माननीया अध्यक्षः इजाजत ही दे रहे हैं, बोलिये।

श्री महेंद्र गोयलः धन्यवाद अध्यक्षा जी। इसमें जो विषय है आज का जो मेरे पास में भेजा गया है ये फैक्ट्री से संबंधित है या एक लाईटों वाला है।

माननीया अध्यक्षः वही है।

श्री महेंद्र गोयलः फैक्ट्री से संबंधित मैं कल बोल चुका था और..

माननीया अध्यक्षः लेबर चाइल्ड वाला है।

श्री महेंद्र गोयलः लेबर चाइल्ड वाला। चलिए आज फिर दोहरा देता हूं मैं। चाइल्ड लेबर के नाम के ऊपर फैक्ट्रियों के अंदर रेड की जाती है। मैं कोई इस हक में नहीं कि चाइल्ड लेबर को कोई भी

व्यक्ति रखे, लेकिन ठेकेदारों के प्रति, जो भी वो व्यक्ति रखते हैं वो ठेकेदार रखता है। लेकिन फैक्ट्री के अंदर पकड़ा जाता है तो वो फैक्ट्री मालिक दोषी हो जाता है, कोई बात नहीं, नियम के तहत दोषी है वो। लेकिन नियम के तहत यदि फैक्ट्री मालिक उसी समय में वो जुर्माना भर देता है तो उसकी डी-सील भी उसी समय में होनी चाहिए। इस केस के अंदर वीरवार के दिन फैक्ट्री सील होती है, शुक्रवार के दिन उसको जुर्माने की राशि बता दी जाती है और पार्टी डीडी बनाकर ऑफिस में पहुंच जाती है, ऑफिस में उससे डीडी लिये नहीं जाते कि अभी तक हमारे पास एफआईआर की कॉपी नहीं आई। ये तो डिपार्टमेंट की जिम्मेवारी है एफआईआर की कापी लेना। और नियम के तहत कोई भी आपने अरेस्ट किया है तो उसको अरेस्ट भी चौबीस घंटे के अंदर-अंदर तो एफआईआर वैसे ही होती है। तो किस नियम के तहत उन बच्चों को वहां कैद रखा गया और एफआईआर का वो क्या टाइम रहा? जब पार्टी ने आपके कहे के मुताबिक वो पैसे भर दिए तो डी-सील उसी समय में होनी चाहिए। मैं माननीय श्रम मंत्री जी यहां पर बैठे हैं, इनका ध्यान दिलवाना चाहता हूं और इसमें स्पष्टीकरण भी चाहूंगा और ऐसे अधिकारियों को आप अपने पास में बुलाए और उनको दिशा निर्देश दें क्योंकि ये छोटी- छोटी फैक्ट्री हैं, दिल्ली की जान हैं। ये लोगों को काम दे रही हैं, राजस्व दे रही हैं और इस प्रकार से इन फैक्ट्रियों को यदि तंग किया जाएगा, अफसरशाही मची रहेगी तो वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। शुक्रवार को डी-सील नहीं की, शनिवार को डी-सील नहीं की, इतवार को कर नहीं सकते, सोमवार के दिन भी शाम के

टाइम में उसको डी-सील किया गया है जब उनकी जेब के अंदर वो कुछ न कुछ डाल दिया गया है, तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है।

तो इस सदन के माध्यम से मैं आपसे यही अनुरोध करता हूं कि माननीय श्रम मंत्री जी इस पर संज्ञान लेते हुए यदि स्पष्टीकरण देंगे तो लोगों के अंदर वो विश्वास बना रहेगा और इस अफसरशाही से जो गलत, बहुत से अफसर बहुत अच्छा काम करना चाहते हैं, ये नहीं है कि सभी के सभी दोषी हैं, बहुत अफसर हैं कि दिल्ली सरकार को बहुत अच्छे से चलते हुए देखना चाहते हैं, लेकिन इस समय के अंदर दुर्भाग्यपूर्ण है कि बहुत ज्यादा संख्या ऐसी भी है कि जो दिल्ली के कामों को रोकने का, इन लोगों को तंग करने का जिन्होंने बीड़ा उठा रखा है। आपने मुझे इस विषय पर बोलने का मौका दिया आपका मैं धन्यवाद करता हूं और माननीय मंत्री जी को आप कहेंगे तो इस पर स्पष्टीकरण भी कर देंगे।

माननीया अध्यक्षः मंत्री जी से आप व्यक्तिगत तौर पर जब अधिकारी हों मुझे लगता है मिल लीजियेगा, वो ज्यादा अच्छे से स्पष्टीकरण देंगे। बोलना चाहेंगे आप, मंत्री जी। मंत्री जी, अभी बोलना चाहेंगे या अपने, बाद में आप समय लेकर मिल लीजियेगा। प्रीति तोमर जी।

श्रीमती प्रीति जितेंद्र तोमरः धन्यवाद अध्यक्षा महोदय आपने मुझे बोलने का मौका दिया। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, इस बार दिल्ली नगर निगम की सदन की बैठक ने एक बड़ी राहत भरी खबर दी। बैठक में

ये फैसला किया गया कि पुरानी संपत्ति में परिर्वतन अवैध निर्माण नहीं माना जाएगा। अध्यक्ष महोदय, अब दिल्ली निवासी अपनी पुरानी संपत्ति को दिल्ली नगर निगम के सहयोग से नियमित करा सकेंगे। इसके लिए संपत्ति मालिकों को अपनी पुरानी संपत्ति में किसी भी तरह का बदलाव करने पर सूचना देनी होगी, जिसके आधार पर निगम इसकी स्वीकृति दे देगा। अध्यक्ष महोदय, कई बार निगम के समक्ष ऐसी जानकारी सामने आई है कि लोग बिना सूचना दिए ही पुरानी संपत्ति में बदलाव करा देते हैं, ऐसी परिस्थिति में निगम उस निर्माण पर कार्रवाई करते हुए उन्हें सील कर दिया करता था। लोगों को इस समस्या से निजात दिलाने के लिए सोमवार को निगम की सदन की बैठक में एक प्रस्ताव लाया गया जिसे सदन ने मंजूरी दे दी है। अध्यक्ष महोदय, दिल्लीवासियों के लिए ये बड़ी राहत की खबर है। मैं दिल्ली नगर निगम को बधाई और शुभकामनाएं देती हूं। धन्यवाद।

माननीया अध्यक्षः जय भगवान उपकार जी।

श्री जय भगवानः माननीया अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे 280 के तहत अति महत्वपूर्ण मुद्दे पर बोलने का अवसर प्रदान किया है उसके लिए धन्यवाद। अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान बवाना विधान सभा के जो पीडब्लूडी रोड हैं उस पर ले जाना चाहता हूं क्योंकि लगातार मैं कई बार शिकायतें कर चुका हूं कि जो मेरे पीडब्लूडी के जो नाले हैं उन पर पानी रहता है हमेशा, पांच गांव के अंदर, एक तो औचंदी गांव के अंदर, एक बवाना गांव के अंदर, शाहबाद दौलतपुर, बरवाला, प्रहलादपुर और कई बार मैं शिकायतें कर चुका हूं। और अभी तक, पिछले डेढ़

साल से कोई समाधान अध्यक्ष महोदय नहीं हुआ। एक चीज कहना चाहता हूं क्योंकि अब लोगों ने भी कहना शुरू कर दिया है क्योंकि लोगों के घरों में सीलन भी आनी शुरू हो गई है क्योंकि वो काफी पुराने नाले बने हुए हैं जिसकी वजह से लोगों के बेसमेंटों में या घरों में, गलियों में पानी भरना शुरू हो गया है। तो माननीय अध्यक्षा महोदय, मैं चाहता हूं कि मैंने पीडब्लूडी को लिखा भी है और अब माननीय हमारी पीडब्लूडी मंत्री जी भी यहां पर बैठी हुई हैं, आपसे निवेदन है मंत्री जी कि आप न इन सभी नालों को दुबारा से तुड़वाकर बनवाए क्योंकि ये जो सभी नाले हैं ये 40-50 साल पुराने नाले बने हुए हैं जिनको 2013-14 में रेनोवट कर दिया गया था। क्योंकि तोड़कर नहीं बनाए गए थे, ईटों के बने हुए हैं, अगर ये मसाले के बनाए जाएंगे तो इन सभी गांव, चाहे मेरा वो शाहबाद है, चाहे वो प्रहलादपुर है, चाहे वो बरवाला है, चाहे वो पूठ है, चाहे वो बवाना है, चाहे वो दरियापुर है, चाहे वो औचंदी है, इन सभी गांवों को राहत महसूस होगी। धन्यवाद।

माननीया अध्यक्षः अखिलेश पति त्रिपाठी जी। विषय है आपके पास।

श्री अखिलेश पति त्रिपाठीः विषय...

माननीया अध्यक्षः मेट्रो के चौथे फेज का विषय लगाया है आपने।

श्री अखिलेश पति त्रिपाठीः अध्यक्ष महोदया, मैं अपने क्षेत्र में चौथे फेज में हो रहे मेट्रो के निर्माण के संदर्भ में जो लोगों को असुविधा हो रहा है उसकी तरफ सदन का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता

हूं। चौथे चरण में जो मेट्रो का निर्माण आजादपुर से लेकर के सीधा, मजलिस पार्क से लेकर के ये मेट्रो स्टेशन जो है र्क खाने तक जाएगा, पूरे के पूरे जो काम कर रही एजेंसी है, सैम इंडिया और इरकॉन, रोडों की हालत ऐसे कर दी है कि डेढ़-डेढ़ फुट के गड्ढे हैं। पहले भी मेट्रो का निर्माण होता था तो एजेंसियों को ये डायरेक्शन होता था कि रोड को सुचारू रूप से रखेंगे, ट्रैफिक का संचालन ठीक से हो ताकि वहां पर जाम न लगे, लेकिन आज हालत क्षेत्र का ऐसा है माडल टाउन विधान सभा में। क्योंकि देश का रोड नंबर-1, जी.टी. करनाल रोड पर वो निर्माण कार्य हो रहा है और पीडब्लूडी का एक फ्लाईओवर भी बन रहा है, मैं धन्यवाद भी करना चाहता हूं आदरणीय मुख्यमंत्री जी को और पीडब्लूडी मंत्री को कि बहुत शानदार डबल-डेकर वहां पर मेट्रो और पुल के साथ निर्माण हो रहा है फ्लाईओवर का भी लेकिन जो कंपनी काम कर रही है, एजेंसियां काम कर रही है उनकी लापरवाहियों की वजह से, मैं कई बार चीफ सेक्रेटरी को भी चिट्ठी लिखा इस संदर्भ में, मेट्रो को भी चिट्ठी लिखा लेकिन अभी तक कोई समाधान नहीं निकला। अध्यक्षा महोदया, मैं क्षेत्र की जनता की तरफ से गुहार करने के लिए खड़ा हुआ हूं कि ये सब रोडों को ठीक किया जाए, जो बहुत गड्ढे हो गए हैं, उन्होंने कोई निर्माण कार्य, क्योंकि पीडब्लूडी कर नहीं पा रही है क्योंकि उनको रोड हैंडओवर हो गया है। अब सारा का सारा मेंटनेंस उनको करना है। पटरियां बिल्कुल टुटी हैं और पॉल्यूशन का हालत ये है कि लोगों को सांस लेने में भी दिक्कत आने लगा है इतना धूल उड़ रहा है। मेरे साथ के बगल के विधान

सभा के साथी बैठे हुए हैं राजेश जी, वो भी जानते हैं, उधर से गुजरते हैं कि कितना जाम लग रहा है अशोक विहार फ्लाईओवर पर और नीचे और इतना पॉल्यूशन। मुझे लगता है कि उनका पॉल्यूशन का चालान भी होना चाहिए और शीघ्र अति शीघ्र अगर उन्होंने उस रोड का निर्माण करके ठीक से सुचारू रूप से ट्रैफिक का संचालन नहीं करते तो उनके खिलाफ एक्शन भी होना चाहिए। बहुत-बहुत धन्यवाद अध्यक्ष महोदया।

श्री राजेश गुप्ताः अध्यक्ष महोदया, इसमें मैं एक लाइन जोड़ना चाहता हूं आपकी अनुमति से।

माननीया अध्यक्षः जी।

श्री राजेश गुप्ताः आपने, बार-बार अगर आप न्यूज में देखें जब पॉल्यूशन का टाइम आता है तो उसमें अशोक विहार का मेंशन होता है कि अशोक विहार में बहुत पॉल्यूशन हो रहा है। अब ऐसा तो संभव नहीं है कि गाजियाबाद से ज्यादा पॉल्यूशन अशोक विहार में हो जाए। लेकिन उस पॉल्यूशन होने की रिजन यही रहता है कि जो वो मेट्रो का काम चल रहा है, जो हमारे साथ अखिलेश पति त्रिपाठी जी ने बताया तो वहीं पर हमारी पोल्यूशन की युनिट लगी हुई है जो उसको चैक करती है और वो लोग इस पर किसी चीजों का ध्यान नहीं देते हैं। पूरा रोड खराब है उसकी वजह से भी पोल्यूशन है साथ में जो कंस्ट्रक्शन साइट है उस पर भी ध्यान नहीं दिया जा रहा। तो मैं आपके माध्यम से ये भी रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि उस पर ध्यान दें क्योंकि अशोक

विहार बहुत ग्रीन एरिया है 697 पार्क्स मेरे पास हैं उसके बाद में भी ये कहना की वहां पोल्यूशन है तो उसका कारण वो है कि वो अब ध्यान से उस पर काम नहीं कर रहे, बहुत-बहुत धन्यवाद।

माननीया अध्यक्षः प्रमिला टोकस जी।

श्रीमती प्रमिला धीरज टोकसः धन्यवाद अध्यक्ष जी, अध्यक्ष जी मेरी विधानसभा में पिछले 6 महीने से काफी जगह पीने के पानी की लाइनें टूट गई हैं बहुत ज्यादा पीने का पानी बर्बाद हो रहा है। सेक्टर-5, आर के पुरम, वसंत इन्कलेव, वसंत विहार, नानकपुरा, शास्त्री मार्किट, मुनिरका डीडीए फ्लैट, मुनिरका गांव आदि जगह पर बहुत लीकेज है और बार-बार जलबोर्ड के अधिकारियों को बोलने के बावजूद मेरी विधानसभा में यह पानी की लाइनें ठीक नहीं की जा रही हैं। मेरी विधानसभा में कई जगह सीवर लाइनें भी रुकी हुई हैं जिसके कारण सीवर की गंदगी गलियों और सड़कों में फैली हुई है उसको भी समय पर साफ नहीं किया जा रहा ये अभी हुआ है। अभी इतना बुरा हाल हो गया है अध्यक्ष जी मुझे लगता है कहीं न कहीं ये अधिकारियों की तो साजिश नहीं है क्योंकि एकदम से इतना बुरा हाल इससे पहले भी विधानसभा चली थी उससे पहले तो ऐसा हाल कभी नहीं हुआ ये अभी इतना बुरा हाल हुआ है पूरी मतलब विधानसभा में। और एक मेरी बस आर.के. पुरम विधानसभा में एक यूजीआर है वसंत विहार में जो दो साल से सूखा पड़ा हुआ है और बार-बार अधिकारियों को बोलने पर उसमें पानी नहीं भरा जा रहा जिसके कारण मेरी विधानसभा वसंत अपार्टमेंट कालोनी वसंत गांव, प्रजापति मोहल्ला आदि जगह पीने के

पानी की बहुत किल्लत है। इस यूजीआर को पानी देने का कार्य किया जाना चाहिए जिससे इन क्षेत्रों में पानी की सप्लाई कर सकें। आपको अवगत कराना चाहती हूं कि पिछले एक साल से मुनिरका और सेक्टर–5 में मेन रोड पालम मार्ग से विवेकानंद मार्ग के पास बने भूमिगत पैदल मार्ग पर लगातार भारी मात्रा में पीने के साफ पानी का रिसाव हो रहा है जिसका पानी बहकर सेक्टर–5 के मेन गेट तक जाता है और वहां पर पानी इक्ट्ठा हो जाता है जिसकी वजह से आने–जाने वाले लोगों को काफी दिक्कतों से गुजरना पड़ता है तथा पानी भरे होने के कारण फिसलन हो रखी है जिस कारण आए दिन छोटे–छोटे बच्चे गिर रहे हैं। अब तो इस पानी के कारण सेक्टर में मच्छर भी पैदा हो रहे हैं। अब कौन सी बीमारी फैल जाए कुछ पता नहीं और इसको अध्यक्ष जी बार–बार हमने जेई, एक्सईएन, एई सभी को हमने इसके बारे में बोला है। अगर आप कोई भी जाएंगे आप वो मेन रोड पर है और इतना बुरा होल हो रखा है। वहां से जब लोग निकलते हैं तो ऐसे रुमाल लगाकर निकलते हैं इतनी बदबू भी आने लग गई है उसमें। एक्सईएन और जेई सबको बताने के बाद भी इस पर कार्यवाही नहीं हो रही है। लगातार भारी मात्रा में पानी का रिसाव होने के कारण लोगों को दिक्कतों से गुजरना पड़ रहा है। साथ ही साथ पानी की कितनी कटौती हो रही है। पानी वैसे ही कम है और जो पीने का पानी है उसमें अधिकारी मुझे नहीं पता क्यों वो उसको बंद नहीं करते हैं। वैसे हमारे एरिये में पानी की दिक्कत है लेकिन जहां लीकेज है लीकेज को बिलकुल ठीक नहीं करते हैं। ये इतना बुरा हाल अभी किया है उन्होंने इससे पहले कभी

नहीं था मुझे नहीं पता की ये अधिकारियों की साजिश है या किसके कहने पर वो ऐसा काम कर रहे हैं। तो मेरा आपसे अनुरोध है अध्यक्ष जी कि मेरी विधानसभा में जहां पर लीकेज है उसको ठीक कराया जाए और जो हमारा यूजीआर है उसमें पानी देने का काम करें ताकी उन लोगों को पानी मिल सके और जो रिसाव है इसको बंद करके हम उनको भी उसमें डालेंगे तो भी हमारी विधानसभा में पानी की पूर्ति हो सकती है, बहुत-बहुत धन्यवाद।

माननीया अध्यक्षः बहुत-बहुत धन्यवाद, सोमनाथ भारती जी।

श्री गिरीश सोनीः जैसे ये आवाज विधानसभा में गूंजती है वैसे ही अब संसद में गूंजेगी बड़ी जल्दी।

श्री सोमनाथ भारतीः साथियों को बहुत-बहुत शुक्रिया अग्रिम बधाई देने के लिए। साथियों आज अध्यक्ष महोदय मेरे आरकेपुरम की विधायक साथी ने जो बात उठाई मैंने तुरंत अभी आदेश दिया है अधिकारियों को आपसे भी तुरंत बात करेंगे। ये बहुत ही चिंताजनक विषय है क्योंकि इस प्रकार की हरकतें नहीं होनी चाहिए। खासकर के सीवर की जो ओवरफ्लो की समस्या है इसको तो अधिकारी तुरंत अटैंड कर सकते हैं। वो मैं सुनिश्चित करूंगा कि तुरंत अटैंड किया जाए। अध्यक्षा महोदया, आज आपने 280 में मुझे बात रखने का मौका दिया उसका बहुत धन्यवाद। जो एक-दो और साथियों ने बात उठाई रोड सेफ्टी की उसको आगे बढ़ाते हुए मैं अपनी बात रखना चाहता हूं। मेरे क्षेत्र में एक यू-टर्न है अरविंदो मार्ग पर इतना फाल्टी उसका स्ट्रक्चर है

और जब मैंने पता किया ये ग्रीन पार्क मेरे और हौजखास एसएफएस फ्लैट्स के पास में है। जब आप ऐम्स की तरफ से आ रहे होते हैं और आईआईटी की तरफ जा रहे होते हैं तो इतना शार्प्ड ऐज्ड वो यू-टर्न है कि कहीं भी किसी का भी एक्सीडेंट हो जाए। जब मैंने पता किया इस प्रकार से क्यों किया गया तो मालूम पड़ा की किसी प्रभावशाली व्यक्ति ने हमारी सरकार आने के पहले उसके घर के आगे वो यू-टर्न न खुले इसलिए उसको ऐसी लोकेशन पर पुश कर दिया कि जनता की जिंदगी को उन्होंने दांव पर लगा दिया है। एक डिपार्टमेंट है यूटीपैक जो कल जून साहब भी उठा रहे थे यूटीटीपीएसी ये डिपार्टमेंट डीडीए के अंतर्गत आता है। तो बार-बार बात वहीं घूमकर पहुंच जाती है कि भई डीडीए के पास, पुलिस के पास, ट्रैफिक पुलिस के पास ये सातों सांसद कान में तेल डालकर सोते रहे हैं 10 साल ये। एक बार भी इन्होंने कुछ भी मुद्दा नहीं उठाया न डीडीए की मुसीबत उठाई न ट्रैफिक की मुसीबत उठाई, न इन्होंने दिल्ली पुलिस से अकाउंटेबिलिटी मांगी। नेचुरल सी बात है कि जब जनता की समस्याओं को नहीं उठाओगे तो समस्याएं वहीं की वहीं बनी रहेगी। साथ में मैं ये भी कहना चाहता हूं कि एक इंटरनेशनल रोड सेफ्टी आर्गनाइजेशन है माननीय मंत्री जी अभी मेंशन कर रहे थे रोड सेफ्टी के ऊपर उसके इंडिया चैप्टर में दिल्ली रीजन का मैं हैड हूं और काफी सारे रोड सेफ्टी के ऊपर हमने कार्यक्रम किये हैं। अगर दिल्ली ट्रैफिक पुलिस, पीडब्लूडी, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट और इंटरनेशनल रोड सेफ्टी आर्गनाइजेशन मिल जाए तो दिल्ली की सड़कों के ऊपर सेफ्टी का प्रबंध किया जा

सकता है। अध्यक्षा महोदया, मैं आपके माध्यम से डीडीए को, यूटीपैक को और माननीय एलजी साहब को रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि इस प्रकार की जितने भी फाल्टी स्ट्रक्चर्स जो रोड पर बनाई गई हैं इस सबका समाधान लाया जाए क्योंकि जान है तो जहान है। अगर किसी व्यक्ति का देहांत होता है, किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है उसके परिवार पर क्या बीतती है उसके परिवार से आप पूछकर पता कर सकते हैं क्योंकि ये चीजें सेलफिश होकर के सरकारी स्ट्रक्चर्स को इस प्रकार से मूव कर देना ये बहुत ही निंदा का विषय है। साथ में मैं ये देख पा रहा हूं कि लोग पूछ रहे हैं कि भई सांसद महोदय जो होते हैं दिल्ली के क्यों आम आदमी पार्टी के और इंडिया एलाइंस के होने चाहिए। मैं ये बात कहना चाहता हूं ऑन-रिकार्ड आज। जब दिल्ली के लोगों के हक मारे जा रहे थे तो ये सांसद तालियां बजा रहे थे वहां पर। जब दिल्ली के अधिकार छीने जा रहे थे जो दिल्ली की जनता ने केजरीवाल जी के रूप में एक सरकार दी इसलिए दी कि हर लिहाज से दिल्ली की जनता की जिंदगी को सुविधाजनक बनाया जाए। तो ये सातों के सातों सांसद अध्यक्षा महोदया इन्होंने एक भी बार दिल्ली की जनता के मुद्दों को नहीं उठाया और यही कारण है कि आज दिल्ली इंतजार कर रही है कि ट्रैफिक पुलिस हो, पुलिस हो, दिल्ली सरकार के अधिकार हों, दिल्ली सरकार की जो सुविधाएं हैं उसको रोकने का जो प्रयत्न किया जा रहा है इसके कारण दिल्ली की जनता इस बार सातों के सातों भाजपा के सांसदों को घर बिठाएगी और इंडिया एलाइंस, आम आदमी पार्टी और जो एलाइंस का सांसद है सातों को भेजेगी वहां पर

और मैं साथियों को कहना चाहता हूं कि ये जो आप यहां से भेजोगे ये सारे लोग मिलकर के इंश्योर करेंगे कि दिल्ली की जनता के अधिकार को वापस लाया जाए।

माननीया अध्यक्षः चलिए, बहुत-बहुत धन्यवाद। मदनलाल जी, मदनलाल जी बीच में हैं। अभी 5 साथियों का नंबर आ सकता है 5 मिनट का समय है तो समय-सीमा को ध्यान में रखते हुए अपना विषय रखें।

श्री मदन लालः धन्यवाद अध्यक्ष महोदया कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। अध्यक्षा जी मेरा क्षेत्र कोटला मुबारकपुर में पिलंजी गांव, बापू पार्क, प्रसादी गली कोटला मुबारकपुर सीवर की दिक्कतों से बहुत ज्यादा परेशान है। उसका सबसे बड़ा शायद कारण यह है कि यह लो-लाइन का एरिया है और जो निकासी का स्थान है वो ऊँचाई पर स्थित है जिसकी वजह से सीवर का डिस्पोजल सही नहीं हो पा रहा है। हम काफी दिन से कोशिश करते रहे हैं कि किसी तरह पुरानी लाइनों को ठीक-ठाक चलाने के लिए मशीनरी का उपयोग करते रहें पर हम उसमें नाकामयाब रह रहे हैं। बार-बार सीवर ओवरफ्लो करने की शिकायत से लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं और लोगों के घर के सामने सीवर का मैला फैला रहता है। हम बहुत दिन से कोशिश कर रहे हैं कि वहां एक बंदोबस्त हो, एक कुंआ टाइप बने जिससे वो सारा का सारा मैला पहले उसमें इक्ट्ठा हो और इक्ट्ठा होने के बाद उसको प्रापर पंपिंग करने के बाद सीवर का जो मेन ट्रंक है उसमें डाल दिया जाए। काफी कोशिश करने के बावजूद भी अफसर इसके लिए न तो तैयार हो

रहे हैं और न ही इस पर ध्यान दे रहे हैं जिसकी वजह से ये क्षेत्र का एरिया पूरा का पूरा सीवर की गंदगी से बहुत ज्यादा परेशान है। तो मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि जलमंत्री इस ओर ध्यान दें और वहां एक ऐसा कुंआं बनवाने की कृपा करें जिससे वहां का डिस्पोजल उस कुंए के द्वारा सीवर की मेन ट्रंक लाइन में किया जा सके, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

माननीया अध्यक्षः पवन शर्मा जी, विषय है आपके पास।

श्री पवन शर्माः धन्यवाद अध्यक्षा महोदया, आपने मुझे 280 के तहत बोलने का अवसर दिया। अध्यक्ष महोदया, मैं आपका ध्यान आदर्श नगर विधानसभा में आजादपुर मंडी की ओर दिलाना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदया आजादपुर मंडी में अदरक और अरबी की धुलाई होती है लगभग 20 अड्डे कहूंगा मैं उनको लगे हुए हैं धुलाई के लिए और उनसे मिट्टी जो सनी होती है अदरक और अरबी मिट्टी में वो मिट्टी सारी की सारी पानी के जरिए, नाले के जरिए भड़ोला गांव के नाले में, झुग्गियों के पास वाले नाले में में आ जाती है और हर रोज अगर दो-दो बार भी नाले साफ किये जाएं तो भी जो है सफाई नहीं होती है जिसकी वजह से भडोला गांव की झुग्गियों में पानी भर जाता है और भडोला गांव की गलियों में भी पानी भर जाता है, आए दिन शिकायत आती है। मैंने पहले भी एपीएमसी में सेक्रेटरी साहब को भी बोला था। तो मैं आपके माध्यम से मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं इसकी ओर कि वहां पर एपीएमसी में जो धुलाई के अड्डे लगे हुए हैं अदरक और अरबी के वहां पर अगर दो टैंक बना दिये

जाएं जिससे धुलाई होकर पानी उन टैंकों के थ्रू निकले, मिट्टी टैंक में बैठ जाए और केवल पानी नाले में आए तो इसका समाधान हो सकता है। तो अध्यक्षा महोदया, मेरी इस समस्या की तरफ गौर किया जाए और इसका समाधान किया जाए, बहुत-बहुत धन्यवाद अध्यक्षा जी।

माननीया अध्यक्षः राजेश गुप्ता जी, पार्क एंड गार्डन सोसायटी।

श्री राजेश गुप्ताः जी, आपका अध्यक्षा जी बहुत-बहुत धन्यवाद आपने एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर मुझे बोलने का मौका दिया। मैं आदरणीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी का और मंत्री गोपाल राय जी का बहुत-बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं क्योंकि जब निगम में हमारी सरकार नहीं थी खासतौर पर मैं उस समय की बात कर रहा हूं इन निगम के पार्को का बहुत बुरा हाल था। मैं एक ऐसी विधानसभा से आता हूं जो अर्बन विधानसभा है और दिल्ली में कदाचित सबसे ज्यादा पार्क्स मेरी विधानसभा के अंदर हैं तकरीबन 697। उन पार्क्स का रख-रखाव एमसीडी बिलकुल नहीं कर पा रही थी और ऐसे में दिल्ली सरकार ने एक योजना निकाली और उसके तहत दिल्ली सरकार ने अपने पास से दिल्ली पार्क्स एंड गार्डन सोसायटी के नाम से वो फंड देना शुरु करा जिससे मेरे यहां के पार्कों की स्थिति बहुत जगह बहुत अच्छी हो गई। बहुत सारे आरडब्लूऐज ने उसमें आवेदन करा और मुझे आज भी याद है कि ट्विटर के अंदर एक बार चला था कि एक बड़ा चंडीगढ़ का खूबसूरत पार्क है और बाद में उसकी जब छानबीन हुई तो पता लगा की वो अशोक विहार के एफ-ब्लॉक का पार्क था। तो ये बहुत ही सौभाग्य की बात रही और दिल्ली सरकार का मैं जितना

धन्यवाद करूं वो कम है उसके लिए। लेकिन इसके साथ ही मैं एक प्राब्लम की तरफ भी ध्यान दिलाना चाहता हूं कि खासतौर से कोरोना के अंदर वो पेमेंट जो थी वो नहीं हो पाई। आरडब्लूऐज ने अपनी जेब से उस पेमेंट को करा हुआ है। वो लोग बहुत धक्के खाते रहे, परेशान होते रहे लेकिन अधिकारी नये-नये कागज मांगते रहे और क्योंकि अधिकारी उसके अंदर जो सार्टीफिकेशन देते हैं वो निगम के थे। उस वक्त का निगम आप जानते हैं कि कितना भ्रष्टाचारी माहौल था उस वक्त का और उन लोगों ने वो सार्टीफिकेट्स नहीं दिये और आज भी वो पैसे रुके हुए हैं। तो मेरा आपके माध्यम से ये निवेदन है कि उसके ऊपर जल्दी से जल्दी काम हो। आरडब्लूऐज बड़ी मुश्किल से 200-200, 300-300 रुपये इक्ट्ठे करती है रेजीडेंस के साथ में वो पैसा उन्होंने उसमें लगाया हुआ है, तो वो सारा पैसा उनको मिल पाए इसकी व्यवस्था अगर आप जल्दी से जल्दी कर देंतो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

माननीया अध्यक्षः बहुत-बहुत धन्यवाद, अल्पकालिक चर्चा की शुरुआत करेंगे मैं नियम, जी।

माननीया राजस्व मंत्री (श्रीमती आतिशी): मैं अध्यक्ष महोदया एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर बात करने के लिए दो मिनट चाहूंगी। अध्यक्ष महोदया, जैसे कि आप जानती हैं कि कुछ दिन पहले दिल्ली की सरकार ने, अरविंद केजरीवाल जी की कैबिनेट ने एक बहुत ही बेहतरीन सोलर पॉलिसी को पास किया था। उसकी घोषणा खुद ही दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने की थी। इस सोलर पॉलिसी में

खासबात यह है कि अब तक दिल्ली की सरकार 200 युनिट बिजली फ्री देती आई है 400 युनिट तक की सब्सिडी देती आई है लेकिन ये सोलर पॉलिसी पहली बार दिल्ली के उन लोगों को जो 400 युनिट से ज्यादा बिजली का प्रयोग करते हैं उनको फ्री बिजली मिल पाए, उनको जीरो बिजली बिल मिल पाए ये सोलर पॉलिसी उसका एक रास्ता खोलती है। ये एक ऐसी पॉलिसी है अध्यक्ष महोदया जिसमें सोलर रूटॉप लगाने पर जितनी बिजली आपकी छत पर बनती है सरकार आपको हर युनिट बिजली पैदा करने के पैसे देती है, आपको इंसेंटिव देती है। अपटू 3 किलोवॉट 3 रुपये युनिट सरकार की तरफ से आपको मिलेगा। 3 से 10 किलोवॉट अगर आप प्रोडयूज करते हैं तो 2 रुपये युनिट आपको सरकार की तरफ से मिलेगा। ये इतनी एम्बीशियस सोलर पालिसी है अध्यक्ष महोदया कि दिल्ली एक ऐसी स्टेट हो जाएगी 2027 तक जो अपनी पूरी बिजली कंजम्प्शन का और आप इस बात को याद रखिये कि दिल्ली एक ऐसा शहर है जिसमें बहुत बढ़ता हुआ बिजली का कंजम्प्शन है। इस सोलर पालिसी के माध्यम से दिल्ली 2027 तक 20 परसेंट अपनी बिजली सोलर एनर्जी के माध्यम से प्रोड्यूस कर पाएगी। ये अरविंद केजरीवाल जी की सोलर पालिसी है। लेकिन आज इस सदन में बहुत दुख के साथ मैं इस बात को रखना चाहती हूं कि इस शानदार सोलर पालिसी को जहां पर 400 युनिट से ऊपर के बिजली के बिल फ्री आ सकते हैं, जिसमें सोलर पालिसी, सोलर एनर्जी जनरेट करने के लिए दिल्ली सरकार पैसा देगी उस सोलर पालिसी को एलजी साहब ने रोक दिया है।ये फाइल काफी दिन पहले एलजी साहब

के पास गई।एलजी साहब इस फाइल को रखकर बैठे रहे। पावर डिपार्टमेंट ने और मैंने खुद एलजी आफिस में कई बार इस मुद्दे को उठाया। हमने उनको कहा कि ये फाइल पास करिये। इस सोलर पालिसी को नोटीफाई करना जरूरी है तभी दिल्ली के लोग इसका फायदा उठा सकते हैं और जब हमने बार-बार सवाल पूछा और इस पॉलिसी की फाइल को वापस भेजने को कहा तो एलजी साहब ने कल देर रात को इसपर ऊल-जुलूल सवाल लगाकर, ऑब्जेक्शन लगाकर इसको वापस भेज दिया। इस बात को समझिये अध्यक्षा जी कि ये ऊल-जुलूल सवाल लगाने का क्या परपज है। इसका परपज यह है कि अब इन सवालों का जवाब देने में वो फाइल घूमती रहेगी, एक अफसर से दूसरे अफसर के पास जाएगी, दूसरे अफसर से तीसरे अफसर के पास जाएगी, तीसरे अफसर से चौथे अफसर के पास जाएगी। उनका एक ही ध्येय है कि आचार संहिता लगने से पहले दिल्ली सरकार की, अरविंद केजरीवाल सरकार की सोलर पॉलिसी की शुरुआत नहीं हो सके, ये एलजी साहब का ध्येय है। ये बहुत दुख की बात है, ये मैं मानती हूं अध्यक्ष महोदया कि अब एलजी साहब जो एक तरह से दिल्ली के गार्जियन हैं जो सबसे highest constitutional authority हैं अब वो विपक्ष की भूमिका जो बिधूड़ी जी को करनी चाहिए वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से राजनीति कर रहे हैं, बैटिंग कर रहे हैं और केजरीवाल सरकार के काम रोकने की कोशिश कर रहे हैं। ये दुख की बात है कि दिल्ली सरकार एक ऐसी प्रोग्रेसिव पॉलिसी लेकर आ रही है जो दिल्ली में इतनी एनर्जी को ग्रीन एनर्जी के तौर पर देगी और मैं इस बात का दुख इस पूरे

हाउस के सामने रखना चाहती हूं कि ऐसी प्रोग्रेसिव पॉलिसी को एलजी साहब द्वारा रोका जा रहा है।

माननीया अध्यक्षः एक घंटे के अंदर जितने ज्यादा से ज्यादा लोगों को बुलवाया गया मैंने उनको बोलने का मौका दिया।

श्री राजेश गुप्ताः उपाध्यक्षा जी मैं इस विषय पर एक निंदा प्रस्ताव लाना चाहता हूं।

माननीया अध्यक्षः राजेश जी मैं आपको अलाउ करूंगी आप बैठिये, बैठिये राजेश गुप्ता जी, जी।

श्री राजेश गुप्ताः माननीय उपाध्यक्षा जी, जैसे आपने सुना कि इतनी अच्छी चीज जिससे पूरी दुनिया जूझ रही है और रोज हम बार-बार देखते हैं कि जिस तरीके से दिल्ली के अंदर पॉल्यूशन की बातें ये करते हैं हालांकि सिर्फ दिल्ली में ही नहीं ये पूरे उत्तर भारत के अंदर ही ये प्राब्लम है और इस बार तो मुंबई के अंदर भी बहुत पॉल्यूशन था। तो आदरणीय केजरीवाल जी का तो धन्यवाद करते ही रहते हैं हर चीज पर वो नई सोच रखते हैं और किस तरीके से दिल्ली को पॉल्यूशन से बचाना है ग्रीन करना है और जैसा मंत्री जी ने बताया इतनी अच्छी पॉलिसी को एलजी साहब ने रोका, बेवजह के सवालों से रोकना चाहते हैं। तो इसके ऊपर हम एक निंदा प्रस्ताव लाना चाहते हैं कि इस तरीके की जो अच्छी पॉलिसीज हैं उसको एलजी साहब रोकते हैं तो हम उसकी निंदा करते हैं और ये प्रस्ताव सदन के सामने मैं

रखना चाहता हूं और सोलर पॉलिसी को जल्दी से जल्दी पास करा जाए इसके लिए उनसे रिक्वेस्ट करता हूं।

माननीया अध्यक्षः श्री राजेश गुप्ता जी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव सदन के समक्ष है,

जो इसके पक्ष में है, वो हां कहें,

जो इसके विरोध में है, ना कहे,

(सदस्यों के हाँ कहने पर)

हाँ पक्ष जीता, हॉ पक्ष जीता निंदा प्रस्ताव पारित हुआ।

अल्पकालिक चर्चा की शुरूआत करेंगे श्री मदनलाल जी।

...व्यवधान...

माननीया अध्यक्षः मैं आपको समय दूंगी, देखिये मैं बहुत ही सुखद माहौल में सदन चलाने का प्रयास करती हूं, बैठ जाइये बिधूड़ी जी। मैं आपको मौका दे दूंगी, मदनलाल जी के बाद दे दूंगी, अब मैंने आदेश कर दिया मदन लाल जी को, आप बैठ जाइये। मदनलाल जी। मदनलाल जी बसों में मार्शलों की पुनः बहाली के संदर्भ में चर्चा, बहाली पर चर्चा प्रारम्भ करें।

अल्पकालिक चर्चा (नियम-55)

श्री मदनलालः धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय 6.12.1962 चाइना का युद्ध हुआ, उस समय हमारी आर्मी ने बॉर्डर पर बहुत बहादुरी के साथ देश की रक्षा की और ये एक ऐसा समय था, जब देश के भीतर भी नागरिक सुरक्षा की जरूरत पड़ी। ऐसे में क्योंकि आर्म्ड फोर्सिसिज का काम देश को बॉर्डर्स पर सुरक्षा प्रदान करने का था, तो नागरिक सुरक्षा के लिए दो डिपार्टमेंटस, दो ओर्गेनाइजेशनस जिसमें एक दिल्ली होमगार्ड और दूसरा नागरिक सुरक्षा के नाम से सिविल डिफेंस की स्थापना की गई। सिविल डिफेंस एक्ट-1968 के द्वारा लोगों की सुरक्षा के लिए पीस काल में, शांतिकाल में और ऐसे समय में जब कोई आपदा आ रही हो, दंगे हो रहे हों, फसाद हो रहे हों, कहीं लोगों को कुछ और तरीके से प्राकृतिक आपदा में जरूरत पड़ती हो, ऐसे समय के लिए सिविल डिफेंस की स्थापना हुई। नागरिक सुरक्षा में 10,792 लोग तैनात हैं, जिनमें से 8574 डीटीसी की और कलैस्टर बसिसिज में दिल्ली सरकार ने एम्पलोइमेंट किए। अगर हम इसका इतिहास देखें तो अध्यक्ष महोदय 11 मई, 2015 को जब सीएम साहब ने ये फैसला लिया कि हमें एक नागरिक सुरक्षा के लिए एक ओर्गेनाइजेशन को दिल्ली की बसों की जिम्मेदारी देनी है, तो उन्होंने इस ओर कदम उठाया और 11 मई, 2015 को बस मार्शलस की कानूनी स्थिति के लिए उन्होंने एक मीटिंग बुलाई। पर चूंकि एक बड़ी सरकार नहीं चाहती थी कि दिल्ली की सरकार नागरिकों की सुरक्षा से संबंधित कोई ऐसे कदम उठाएं जो कदम पॉपुलर कहलाएं, तो उसी को रोकने के लिए

डिरेल करने के लिए उसको स्कीम को जड़ से ही खत्म करने के लिए शुरूआती तौर पर 11 मई, 2015 को बस मार्शलस की कानूनी स्थिति पर आपत्ति उठाते हुए होमगार्ड के डीजी ने एक पत्र लिख दिया और उन्होंने 17/6/2015 को 4 हजार होमगार्डस के डैप्लोएमैंट के लिए आदेश पारित किया। ये कदम था कि दिल्ली सरकार की उस पोपूलर स्कीम को अपने हाथ में ले लेने का कि दिल्ली की सरकार ना करें, माननीय केजरीवाल जी ना करें, बल्कि किसी तरह इसको अपने हाथ में लेकर रोकने का काम शुरू कर दिया। उसके कुछ ही दिनों बाद 18 जून, 2015 को डायरेक्टर जनरल होमगार्ड द्वारा एक प्रॉमिस की गई कि वो दो हजार गार्डस 22 जून, 2015 तक उपलब्ध कराएंगे, जून, 2015 तक। अध्यक्ष महोदय 16 सितम्बर, 2015 को सीएम साहब को ये बात पता थी अच्छी तरह कि ये उस स्कीम को लटकाने के लिए एक नया पैरलल चैनल चलाया गया है। उन्होंने एक मीटिंग प्रेजाइड की और उसके दो ही दिन बाद ट्राँस्पोर्ट मिनिस्टर ने एक मीटिंग इसी संदर्भ में प्रेजाइड की और इस पर चर्चा की और इस स्कीम को कैसे लागू करें उसके लिए प्रयत्न शुरू हो गए। 6 नवम्बर, 2015 रेवेन्यू डिपार्टमेंट को रिक्वैस्ट की गई कि वो 5 हजार सिविल डिफेंस वॉलिइंटर्स की एक टीम तैयार करे जो बसिसिज में मार्शलस के बतौर तैनात किए जा सकें। 24 नवम्बर, 2015 को रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने इसमें अपनी कन्सैंट दी, हाँ भरी और सिविल डिफेंस के लिए डीएम सिविल डिफेंस को एक चिट्ठी लिखी, सिविल डिफेंस डायरेक्टरेट ने की 5 हजार सिविल डिफेंस के वॉलियंटर्स की नियुक्ति के लिए तैयारी की जाए। इसके कुछ

ही दिन बाद 12 दिसम्बर, 2017 को दो साल बाद, पता चला कि 4500 बस मार्शलस की रिक्वायरमेंट है जबकि उस समय तक 2253 वॉलियटर्स ही उपलब्ध थे। इसके बाद फैसला लिया गया कि चूंकि होमगार्ड का डायरेक्टरेट ज्यादा प्रेस कर रहा था और वो जानबूझकर इसमें घुस रहे थे जिससे इसको, जैसा मैंने कहा कि उनकी हमेशा कोशिश ये रही कि इस स्कीम को रोका जाए। तो उन्होंने अल्टीमेटली ओब्जैक्ट किया और उसके बाद दिल्ली सरकार ने फैसला किया कि अच्छा मान लेते हैं होमगार्ड के फिफ्टी परसैंट, सिविल डिफेंस के फिफ्टी परसैंट, पर लाओ तो सही, करो तो सही। उसके बाद और दो साल गुजरे लगभग 7 अगस्त, 2019 को डिसाइडिड किया गया कि डीटीसी बसों और कलस्टर बसों में होमगार्ड और सिविल डिफेंस और एक्स सर्विसमैंन के लोग लगा दिए जाएं, दिल्ली गवर्नमेंट मान गई, कि लगाओ तो सही। अध्यक्ष महोदय 9.8.2019 रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने रिक्वैस्ट किया कि 9750 सिविल डिफेंस के लिए भर्ती शुरू की जाए। 4 सितम्बर, 2019 दिल्ली के होम मिनिस्टर ने एक मीटिंग बुलाई और होम डिपार्टमेंट ने उसमें प्रोमिस की कि वो 5500 होमगार्ड के वॉलियटर्स उपलब्ध कराएंगे। अध्यक्ष महोदय, 18 सितम्बर, 2019 दो हफ्ते बाद ट्रांस्पोर्ट मिनिस्टर ने डायरेक्टर जनरल होमगार्ड की मीटिंग में ट्राँस्पोर्ट मिनिस्टर की मीटिंग में डायरेक्टर जनरल होमगार्ड ने संकेत दिया कि वो 5 हजार से ज्यादा वॉलियंटर्स नहीं दे पा रहे हैं और राष्ट्रीय सैनिक बल के सचिव ने प्रोमिस किया कि वो 4 हजार, 10 अक्तूबर, 2019 तक दे पाएंगे। 19 अक्तूबर, 2019 को ट्राँस्पोर्ट मिनिस्टर के साथ फिर एक

मीटिंग हुई जिसमें डायरेक्टर जनरल होमगार्ड ने कहा कि वो 4 हजार वॉलियटरस देंगे और रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने कहा कि 4200 सिविल डिफेंस के लोग वो दे देंगे। अध्यक्ष महोदय अगर हम इस बात को देखें कि 2015 में जो सरकार की मंशा थी, कि दिल्ली के लोगों को सुरक्षा दी जाए, क्योंकि आए दिन हम सुन रहे थे बसों में लगातार झगड़े की, मार-पिटाई की, कत्ल की, बलात्कार की शिकायतें आ रही थी और दिल्ली बड़ा पैनिक थी। पूरे देश में जहां दिल्ली सबसे ज्यादा अच्छी और सुरक्षित मानी जाने वाली सिटी होनी चाहिए, दुनिया में जहां हम अपने देश को बहुत ज्यादा विकासशील, विकसित और बहुत ज्यादा आगे बढ़ोत्तरी वाला देश प्रजेंट करने की कोशिश करते हैं, पर जब भी दिल्ली में कानून व्यवस्था की बात आ रही थी तो हम शायद सबसे ज्यादा पिछड़े हुए माने जा रहे थे, क्योंकि हमारे यहां वारदातें बसों में ज्यादा हो रही थी और खासकर बहुत ज्यादा इन्सीडेंट जेबकतरों की आती थी, बहुत सारी बातें महिलाओं के साथ बदतमिजी की आ रही थी। तो ये 4 साल जो इसमें लगे केवल इसलिए लगे कि बड़ी सरकार की इसमें काम रोकने की इच्छा लगातार चलती रही और उसी के चलते दिल्ली सरकार की वो पॉपूलर स्कीम 2019 तक, 19 अक्तूबर, 2019 तक केवल पेपरों पर चलती रही, लोगों की इम्पलोइमेंट नहीं हुई। इसके बाद अध्यक्ष महोदय, 25 नवम्बर, 2019 टोटल उस समय 8259 बस के मार्शलस थे, 4186 इसमें होमगार्ड थे, 3634 इसमें सिविल डिफेंस लगे और 439 एक्स सर्विसमेन लगे। इसके लिए सरकार ने 11 मार्च, 2021 को कि इनके बजट का अलोकेशन सही तरीके से हो पाए, क्योंकि

उससे पहले बजट विधानसभा के द्वारा दिया जा रहा था। अब चूंकि बसों में नियुक्ति हो गई थी, तो ट्रांस्पोर्ट डिपार्टमेंट की जिम्मेवारी थी कि वो इसके लिए बजट का प्रावधान करेंगे। तो 11 मार्च, 2021 को बस मार्शलस के लिए दो बजटों का अलोकेशन किया गया, दो बजट बनाए। एक डीटीसी की बसों के लिए और एक कलस्टर्स बसों के लिए। इसी दौरान दिल्ली सरकार ने एक पब्लिक इंट्रस्ट लीटिगेसन जिसका नम्बर 2559/19 था में सरकार ने आश्वासन दिया कि वो बस मार्शलस की पेंडिंग सैलरी को देंगे और उसके साथ ही उन्होंने 4.10.2023 को ये वायदा किया कि उनको देंगे और उनकी सर्विसिसिज को सुरक्षित रखेंगे और जब बड़ी सरकार को लगा कि दिल्ली सरकार मान नहीं रही है, वो बसों में मार्शल को लेकर बहुत ज्यादा संज्ञानशील है तो 4.10.2023 को डीसी हैडक्वाटर ने एक आदेश पारित कर दिया कि सिविल डिफेंस का काम केवल आपदा में लोगों की सुरक्षा करने का है, आपदा से निपटने का है, लिहाजा डीटीसी की और कलस्टर बसों में हम सिविल डिफेंस की नियुक्ति को अवैध मानते है। ये बड़ा अटपटा सवाल था। आपदा क्या है? आपदा केवल आएगी तभी करेंगे या आपदा को बचाने के लिए भी हम किसी एजेंसी का इस्तेमाल कर सकते हैं जैसे 1962 के युद्ध के बाद ये प्रोक्योर की गई, ये संगठन बनाया गया कि कोई आपदा ना हो और आपदा हो तो उससे निपटा जाए। अध्यक्ष महोदय 11 अक्टूबर, 2022 मुख्यमंत्री जी ने सिविल डिफेंस के वेतन के भुगतान के लिए नाराजगी जताई, कि आप इनका भुगतान नहीं कर रहे हैं क्योंकि तब तक सिविल डिफेंस के वॉलियटियर्स में बड़ा पैनिक आ

गया था। ये वो लोग हैं जो बेचारे अपना रोजी-रोटी कर रहे हैं, अगर हम इस दौरान देखें तो हमारी बड़ी पॉपूलर सरकार ने लोगों की नई भर्तियाँ बंद कर रखी हैं, वो पुराने जो हमारे सरकारी अधिकारी हैं, रिटायरमेंट होने के बाद उनको कन्सलटेंट रखते हैं। उन बुजुर्गों का तो ध्यान रख रहे हैं, पर जो नई जनरेसन आ रही है, मैं कई-कई बार अपनी विधानसभा में लोगों से पूछता हूं सरकारी अधिकारियों से, सरकारी कर्मचारियों से कि उनमें कोई भाग्यवान ऐसा है जिसके बेटे को सरकारी नौकरी मिल गई है। सब अपना मुंह नीचे कर लेते है, उनकी मौन स्वीकृति इस बात की द्योतक है कि ऊपर वाली सरकार कोई नौकरी नहीं दे पा रही है। ऐसे में इन सिविल डिफेंस के लोगों ने जहां एक तरफ दिल्ली के जो हमारी माँ-बहन-बेटी बसों में सफर करती हैं, जो हमारे बच्चे सफर करते हैं, जो हमारे बुजुर्ग सफर करते हैं, उनकी सुरक्षा और सहुलियत के लिए, वो सुबह से शाम तक मेहनत करते हैं, उसके बदले में जो वेतन मिलता है अगर उसको भी वेतन ना मिले तो अपना घर कैसे चलाएंगे? तो मुख्यमंत्री जी ने उस पर नाराजगी व्यक्त की और उसके बाद सरकार ने ये भी फैसला किया कि जो दिल्ली की सरकारी बसिसिज हैं उनमें थ्री लेयर सिक्योरिटी वो चालू रखेंगे।

माननीया अध्यक्षः कम्पलीट कीजिए।

श्री मदन लालः जी, एक सीसीटीवी कैमरा, दूसरा पैनिक बटन और तीसरा बस मार्शलस का। इस बात के लिए अध्यक्ष महोदया 21 अक्टूबर, 2023 एलजी साहब एग्री भी कर गए, पर एलजी साहब एग्री कर गए जैसे बहुत चीजों के लिए एग्री करते हैं, पर नीचे के अफसर

तो साइलेंट हैं, उन्हें पता है कि एलजी साहब भले ही गर्दन हाँ में हिला दें, उन्होंने करना नहीं है क्योंकि उसके पीछे एक षड्यंत्र चला आता है और 31 अक्टूबर, 2023 को रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने सिविल डिफेंस के वॉलियटियर्स की सर्विसिज समाप्त कर दी और समाप्त करने के पीछे लोजिक क्या था कि आपदा के समय में काम आने वाली सर्विसिज हैं, यहां होमगार्ड लगाए जाएं। होमगार्ड का जो जन्म है वो भी चाइना वॉर के बाद ही हुआ था, कि लोगो को एक सुरक्षा एजेंसी ऐसी हो जो नागरिक सुरक्षा के लिए काम करे। अब सिविल डिफेंस और होमगार्ड में तो कोई ज्यादा बड़ा अंतर है नहीं। पर जानबूझ के क्योंकि ये स्कीम माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की थी, लोगों को भले के लिए थी, लिहाजा उसको खत्म करना था और एक नई एजेंसी को उसमें इन्सर्ट करना था जो कभी आएगी नहीं। 2015 में जो सीएम साहब जो स्कीम लाना चाहते थे वो 2019 तक अप्लाई ही नहीं हुई, उसके बाद वो 2023 में समाप्त की गई। 1 नवम्बर, 2023 को रेवेन्यू मिनिस्टर ने वो सेवा समाप्त करने वाले सर्कुलर में संशोधन करने के लिए एक रिक्वैस्ट की। उन्होंने लिखा कि जब तक होमगार्ड के वॉलियंटर्स को आप बसिसिज में डैप्लोए नहीं करते तब तक आप इन्हीं लोगों को सर्विसिसज में डीटीसी बसों में कन्टीन्यू कर दें। 2015 से 2022 तक ये सर्विस कन्टीन्यू रही है, स्मुदली रही है। परन्तु अक्टूबर, 2023 के बाद जब ट्रांस्पोर्ट डिपार्टमेंट ने प्रपोजल दिया कि अब हम इसका पैसा देंगे, क्योंकि ये लोग डीटीसी की बसों में काम कर रहे हैं, उसके बाद ये दिक्कत आई और फाइनेंस डिपार्टमेंट ने, एक इसमें क्वायरी रेज करनी

शुरू कर दी, ये कहके की इसकी तो एलजी साहब से अप्रूवल ही नहीं ली है, ये तो कैबिनेट में ही नहीं आई है। इसके बाद इल्लीगल डैप्लोएमेंट मानते हुए, उन्होंने जो आदेश पारित किया था, माननीय रेवेन्यू मिनिस्टर ने अपने विभाग को लिखा कि इसके बारे में वो कैबिनेट नोट प्रेजेंट करें जिससे इसको सिविल डिफेंस के लोगों की रूकी हुई सेलरी दी जा सके और इनकी सर्विसिसज को कन्टीन्यू किया जा सके, जब तक होमगार्ड के वॉलिनटियर्स इसमें ना आ जाएं। ये प्रपोजल हो सकता है सालों-साल लगे, हो सकता है ये अगली विधानसभा में भी डिस्कस कर रहे हों, वो होमगार्ड के वॉलिंटियर्स ना लगने हैं, ना लग रहे हैं, ना लगने की उम्मीद है। अध्यक्ष महोदया ये लोगों के सौतेला व्यवहार है। बड़ी सरकार को लगता है कि दिल्ली के लोगों ने चूंकि उनको नहीं चुना है, इसे लोगों से बदला लेना है तो वो बार-बार माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी सभी स्कीमों को by this way or the other बंद करने की और रोकने की कोशिश लगातार करते हैं। आज मेरी विधानसभा के यहां कई वॉलिंटीयर्स आए हुए हैं, वो बेचारे बेरोजगार हैं, क्योंकि जिस समय उन्होंने यहां सिविल डिफेंस की नौकरी शुरू की थी, उस समय अब से 10 साल, 12 साल, 15 साल पहले उस समय वो यंग थे, अभी उनकी उम्र नौकरी करने लायक से ऊपर हो गई है।

माननीया अध्यक्षः अब कम्पलीट कीजिए।

श्री मदन लालः सरकारी नौकरियाँ और मिल नहीं रही हैं, बड़ी सरकार की मेहरबानी से। ये नौकरी खत्म हो गई है, उनकी उम्र ज्यादा हो रही है, परिवार में जीने के साधन खत्म हो रहे हैं। ऐसे में दिल्ली

के लोग जो भय में, खासकर बसों में जो महिलाएं हमारी बहन-बेटियाँ, हमारे बुजुर्ग, हमारे बच्चे, जो अपने आपको असुरक्षित महसूस करते हैं और ये इसलिए भी है।

माननीया अध्यक्षः बहुत सारे वक्ता हैं।

श्री मदन लालः मैं आधा मिनट नहीं लगाऊंगा। दिल्ली की बसों में सफर करने वाले लोग और दिल्ली में आए दिन हम अखबारों में पढ़ते हैं कि सिविल डिफेंस के वॉलियंटर्स की सूझबूझ से आज बस में हादशा होते हुए बचा। आज किसी महिला के साथ छेड़खानी रूकी, आज किसी के साथ चाकूबाजी रूकी, आज किसी की जेब कटते रूकी, आज किसी का नुकसान होते बचा। ये लोग अपनी जान की परवाह किए बिना देश की सेवा में लग रहे हैं, दिल्ली के लोगों की सेवा में लग रहे हैं। परंतु बड़ी सरकार नहीं चाहती कि ये सरकार पॉपुलेरिटी के काम करे और साथ के साथ लोगों को रोजगार भी दे। इसलिए माननीय अध्यक्ष महोदया मेरा आपसे निवेदन है आपके माध्यम से कि सरकार इस बारें में और जो भी कदम उठा सकती हो, हमको ये स्कीम तब तक लागू करवानी चाहिए जब तक होमगार्ड की नियुक्ति नहीं होती।

माननीया अध्यक्षः चलिए, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री मदन लालः हम तो चाहते हैं कि जो सिविल डिफेंस के लोग है उन्हीं लोगों को होम गार्ड में वैसे के वैसे ही भर्ती कर लिया जाए, नाम ही तो बदलना है। दोनों सेवा एक जैसी हैं, दोनों सेवाओं के

लिए कोई परीक्षा नहीं है, दोनों सेवाएं एक जैसी हैं, एक जैसी तनख्वाह है। लिहाजा उन लोगों को जो सिविल डिफेंस में काम कर रहे थे उन लोगों को या तो सिविल डिफेंस में कन्टीन्यू करें या सिविल डिफेंस का नाम होमगार्ड के लिए करके उनको नौकरी में दें, जिससे लोगों की बसों में सुरक्षा की भावना ज्यादा अच्छी रहे, माननीय केजरीवाल जी का बहुत-बहुत धन्यवाद, आपका धन्यवाद।

माननीया अध्यक्षः बहुत-बहुत धन्यवाद मदन लाल जी। ऋतुराज जी। अच्छा दो ही मिनट बोलेंगे आप। ठीक है एक बार इनको बुलवा देते हैं, 5 मिनट में खत्म करिएगा, बैठ जाइये ऋतुराज जी इनके बाद आपका।

श्री रामवीर सिंह बिधूड़ी (माननीय नेता, प्रतिपक्ष): आदरणीय सभापति महोदया, इस सदन के बहुत ही वरिष्ठ सदस्य आदरणीय श्री मदन लाल जी द्वारा नियम-55 के तहत जो चर्चा शुरू की गई है कि दिल्ली के जिन मार्शलस को नौकरी से निकाल दिया गया। इसके साथ हमारे सिविल डिफेंस वॉलियंटर्स के साथ-साथ बस मार्सलस इनकी बहाली हो, इसके लिए भाजपा विधायक दल उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर उनकी लड़ाई को लड़ रहा है। आदरणीय सभापति महोदया मैं इसके साथ-साथ आपके माध्यम से सरकार से प्रार्थना करूंगा कि दिल्ली में xxxx[1]

माननीया अध्यक्षः ठीक है, दो मिनट में खत्म करिए।

श्री रामवीर सिंह बिधूड़ी (माननीय नेता, प्रतिपक्ष): xxxx[1]

माननीया अध्यक्षः ये विषय क्या है।

श्री रामवीर सिंह बिधूड़ीः देखिये, इस हाउस में ये, मेरी बात सुनिए।

माननीया अध्यक्षः आपको एक सैकंड, बिधूडी पहले, बिधूड़ी मेरी बात सुन लीजिए।

श्री रामवीर सिंह बिधूड़ीः मेरी बात सुनिए।

माननीया अध्यक्षः आप पहले मेरी बात सुनिए।

श्री रामवीर सिंह बिधूड़ीः मैं दो मिनट में अपनी बात खत्म।

माननीया अध्यक्षः आपने बोला मुझे पहले समय चाहिए।

श्री रामवीर सिंह बिधूड़ीः देखिये, देखिये मेरी बात तो सुन लीजिये।

माननीया अध्यक्षः जो विषय।

श्री रामवीर सिंह बिधूड़ीः आप मेरी बात तो सुन लीजिये, xxxxxx[1]

माननीया अध्यक्षः ये विषय नहीं है विषय मार्शल्स का है।

---

[1] चिन्हित अंश अध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार सदन की कार्यवाही से निकाले गए।

श्री रामवीर सिंह बिधूड़ीः इस पर, इस पर उन्होंने कहा तैयार होकर आयें, चर्चा करायेंगे तो आप केवल केवल.. नहीं-नहीं-नहीं।

माननीया अध्यक्षः आज बस मार्शल्स पर चर्चा हो रही है आप बात करिये।

श्री रामवीर सिंह बिधूड़ीः नहीं-नहीं-नहीं

माननीया अध्यक्षः ये जो बोल रहे हैं निकालें सारा कार्यवाही से।

श्री रामवीर सिंह बिधूड़ीः xxxxxx[1]

माननीया अध्यक्षः कार्यवाही से सब निकाल दिया जाये।

श्री रामवीर सिंह बिधूड़ीः xxxxxx1

माननीया अध्यक्षः बिधूड़ी जी ने बस मार्शल्स के अलावा जो भी कहा है वो सब कार्यवाही से निकाला जाये।

श्री रामवीर सिंह बिधूड़ीः xxxxxx[1]

माननीया अध्यक्षः बहुत-बहुत धन्यवाद, कुलदीप कुमार जी, ऋतुराज जी बैठिये, कुलदीप कुमार जी, कुलदीप कुमार जी अपना वक्तव्य रखेंगे।

श्री कुलदीप कुमारः धन्यवाद, धन्यवाद अध्यक्षा जी।

माननीया अध्यक्षः बस मार्शल्स के अलावा बिधुड़ी जी ने जो भी वक्तव्य रखा उसे कार्यवाही से निकाल दिया जाये।

---

[1] चिन्हित अंश अध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार सदन की कार्यवाही से निकाले गए।

..व्यवधान..

श्री कुलदीप कुमारः अरे बिधूड़ी जी बैठ जाओ।

माननीया अध्यक्षः कार्यवाही से निकाला जाये हर एक शब्द, जो बस मार्शल्स के अलावा जो भी शब्द, शब्दावली रखी है बिधूड़ी जी ने, कुलदीप जी, अपना वक्तव्य रखें।

श्री कुलदीप कुमारः धन्यवाद अध्यक्षा महोदय, आपने आज नियम-55 के तहत बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर मुझे चर्चा में भाग लेने का समय दिया और देखिये बिधूड़ी जी चले गये और हमें पता था, हमें स्पष्ट था इसलिये माननीय मंत्री सौरभ भारद्वाज जी ने कहा था कि जिस दिन इस सदन के अंदर बस मार्शल के ऊपर, डीसीडी वॉलेंटियर्स के ऊपर चर्चा होगी उस दिन तैयारी से आईयेगा। अब तैयारी तो थी नहीं कुछ, क्या तैयारी थी उनके पास, इसलिये सदन छोड़कर भाग गये और यहां हमारे वो डीसीडी वॉलेंटियर्स भी होंगे बस मार्शल मेरी बात सुन रहे होंगे। आप देख लीजिये भाजपा का चरित्र क्या है। तो अध्यक्षा जी आपने मुझे इस पर बात रखने का मौका दिया, सबसे पहली बात तो जो डीसीडी वॉलेंटियर्स है जो हमारा बस मार्शल है, दिल्ली के अंदर सबने देखा कि दिल्ली के अंदर एक बहुत बड़ा केस हुआ 17 दिसम्बर, 2012 को, 17 दिसम्बर 2012 को दिल्ली में चलती हुई बस के अंदर एक 23 साल की बेटी के साथ दुष्कर्म हुआ और दुष्कर्म के बाद तब हम लोग सत्ता में नहीं थे, ना हमारी सरकार थी। हम सब लोगों ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसके लिये आंदोलन किया और आंदोलन करके उसके बाद जब

दिल्ली के अंदर हमारी सरकार बनी तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने निश्चित किया कि महिलाओं की, हमारी बहन-बेटियों की सुरक्षा हो और बहन-बेटियों की सुरक्षा के लिये जो हमारी डीटीसी की बस थी उन डीटीसी बस के अंदर बस मार्शलों की तैनाती की गई। दिल्ली के अंदर जगह-जगह डीसीडी फोर्स की भी तैनाती की गई, इसीलिये की गई ताकि हमारी बहन-बेटियां सुरक्षित रह सकें। बसों के अंदर पैनिक बटन भी लगाये गये, कैमरे भी लगाये गये लेकिन आज मुझे इस सदन में कहते हुये बड़ा दुःख हो रहा है कि मैंने सुना कि किसी ने ये कहा की अगर बस के अंदर पैनिक बटन लगा हुआ है, कैमरे लगे हुये हैं तो बस मार्शल्स की जरूरत नहीं है। अब तो मैं कहता हूं कि दिल्ली पुलिस को दिल्ली से हटा दो, दिल्ली पुलिस वाले कहते हैं हमने दिल्ली में जगह-जगह कैमरे लगा दिये तो क्या दिल्ली पुलिस को घर बैठा दोगे आप? क्या अगर कहीं पर आप कैमरे लगा दोगे तो वहां से आप वहां की फोर्स हटा दोगे? क्या आप ये तय करना चाहते हो कि पहले कोई केस हो जाये, किसी बहन-बेटी की इज्ज़त लुट जाये, किसी बहन-बेटी का बलात्कार हो जाये और उसके बाद वो कैमरे में आ जाये, बस आप आरोपी को पकड़ लो। आपका मकसद क्या आरोपी को पकड़ना है? आपका मकसद हमारा मकसद इस सरकार का मकसद आरोपी को पकड़ना नहीं है उस क्राइम को रोकना है ताकि दिल्ली की एक भी बहन-बेटी के साथ वो बलात्कार ना हो सके, वो घटना ना हो सके, इसलिये बस के अंदर ये एक पूरे देश में मॉडल स्थापित किया गया कि बहन-बेटी की सुरक्षा के लिये कोई दौबारा निर्भया का केस ना

हो इस दिल्ली के अंदर, इसके लिये बस मार्शल की नियुक्ति की गई। और मुझे तो बड़ा दुःख होता है कि चार महीने से वो बस मार्शल, वो डीसीडी के वॉलेंटियर्स, वो डीसीडी के वॉलेंटियर्स जिन्होंने कोविड काल के अंदर इस दिल्ली के लोगों की सेवा की, दिल्ली के अस्पतालों में सेवा करी, जगह-जगह जहां पर लॉक डाउन लगा था वहां पर सेवा करी, उन बस मार्शलों ने बस के अंदर सेवा करी, तैनाती करी उनको जहां आवार्ड देना चाहिये था, उनको आवार्ड लैफ्टिनेंट गर्वनर ने क्या दिया कि उन्होंने उनको नौकरी से निकाल दिया, उनको नौकरी से हटा दिया और मैं हर बार कहता हूं कि नौकरी से हटाना कोई एक बार का फैसला नहीं है, आप अगर पिछले दो सालों में देखोगे अध्यक्षा जी, तो पिछले दो सालों के अंदर हर टीवी डिबेट पर चाहे वो देश की संसद के अंदर भी, भाजपा के सांसद, चाहे वो बीजेपी के विधायक हों, वो हर जगह एक बात कहने लगे कि ये जो डीसीडी के वॉलिन्टियर हैं ये आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं। क्या 10 हज़ार लोग किसी पार्टी के कार्यकर्ता हो सकते हैं और दिल्ली वालों ने तो आम आदमी पार्टी को अरविंद केजरीवाल जी को 67 सीटें दी हैं, दिल्ली का हर आदमी आम आदमी पार्टी को पसंद करता है, दिल्ली का हर आदमी आम आदमी पार्टी को चाहता है तो क्या आप पूरी दिल्ली के 2 करोड़ लोगों को हटा दोगे, आप दिल्ली से रोज़गार खत्म कर दोगे? आपने ये कहकर और देश की संसद में रमेश बिधूड़ी जी उनके सांसद हैं उन्होंने कहा कि ये तो आम आदमी पार्टी के वॉलेंटियर हैं। अरे आप ऐसा आरोप कैसे लगा सकते हो किसी के ऊपर और इनकी इस मानसिकता ने, मैं आपको

एक वाक्या याद दिलाता हूं जब दिल्ली में बाढ़ आई तो आईटीओ के ब्रिज के पास पानी भरा था उसके ऊपर आज तक की वैन खड़ी हुई थी उस वैन में विजेंद्र गुप्ता जी आज हैं नहीं सदन में, उनको सदन की मर्यादा भंग करने के चक्कर में बाहर किया हुआ है, तो उन्होंने वहां खड़े होकर कहा तो मुझसे पूछा भई आपकी क्या तैयारी है इस बाढ़ में, तो मैंने कहा हमारे डीएम लगे हुये हैं, हमारे एसडीएम लगे हुये हैं, हमारे सिविल डिफेंस के वॉलेंटियर लगे हुये हैं सेवा में, कह रहे वो तो केजरीवाल की फोर्स है, वो तो केजरीवाल के लोग हैं। मैं तो सैल्यूट करता हूं केजरीवाल जी की फोर्स को जो आपदा के समय में दिल्ली के लोगों के साथ खड़ी रहती है। मैं तो धन्यवाद करता हूं। आप भी बनाओ ना ऐसी फोर्स, आप भी बनाओ कि जो लोगों की सहायता करे ,जो लोगों की मदद करे, जो लोगों को जीवन दान दे । तो ये जो हमारे बस के मार्शल हैं इनको तो हटाया-हटाया जो दिल्ली के अलग-अलग विभाग में लोग काम कर रहे थे एक और बताता हूं गोताखोर। जब हमारे यहां कोई नाले में डूब जाता है मेरे यहां हिंडन नहर आती है यूपी से, यूपी irrigation की नहर हैऔर आये दिन उसमें ये हादसे होते रहते हैं। तो जैसे कोई उसमें डूब जाता है तो हम तुरंत फोन करते हैं एसडीएम साहब को कि भई आप यहां पर गोताखोरों को भेज दो। आप सोचो वो गोताखोर उसमें घुसते हैं, कोई जिंदा बच पाता है कोई नहीं बच पाता उसकी बॉडी को ढूढ़ने में दो-दो दिन लगते हैं ठंड का टैम्परेचर होता है और वो वहां से उसको निकालकर लेकर आते हैं और घर वालों को शांति होती है कि हमारे परिवार के हमारे बेटे

की जो लाश थी वो मिल गई या वो जिंदा बच गया। उन गोताखोरों को हटा दिया, उन गोताखोरों को भी हटा दिया। लैफ्टिनेंट गर्वनर साहब आप भाजपा के चक्कर में इतने वो हो गये कि आप दिल्ली के बेटे-बेटियों से, 10 हज़ार से बड़ी संख्या के लोगों से, आपको रोज़गार देना चाहिये था आप रोज़गार छीनने लग गये, आपने उनको बाहर बिठा दिया। तो मैं तो कहना चाहता हूं इस सदन में कि जिन लोगों को इन्होनें निकाला है मार्शलों को और डीसीडी वॉलेंटियर को उनकी तुरंत प्रभाव में उनको नौकरी पर वापस रखा जाये और ये मैं इस सदन के माध्यम से कहता हूं कि उनको वापस नौकरी पर बहाल किया जाये और मैं उन्हें जिम्मेदारी से कहता हूं कि हम सब लोग, मैं उनके धरने पर गया हूं उपाध्यक्षा जी, मैं तीन-तीन बार उनके धरने पर गया हूं। वो लोग किस तरह से अपने बच्चों की पढ़ाई करा पा रहे होंगे। उनको वेतन नहीं मिला चार-चार महीने से, वो चार महीने से धरने पर बैठे हुये हैं, क्यों बैठे हुये हैं? क्योंकि उनका रोज़गार चला गया। जिन लोगों ने आठ-आठ साल, और फिर बता दूं ये सरकार जब आई तब इन लोगों को बस में मार्शल लगाया गया। ये कहते हैं रोज़गार किसको दिया? हमने इनको रोज़गार दिया 10 हज़ार लोगों को और आपने उन 10 हज़ार लोगों का रोज़गार छीन लिया। हम रोज़गार देने वाले हैं अरविंद केजरीवाल जी, आप रोज़गार छीनने वाले हो। तो भाजपा का चेहरा, भारतीय जनता पार्टी का चेहरा इस पूरी दिल्ली के सामने पर्दाफाश हो चुका है कि इन्होंने किस साजिश के तहत किस मानसिकता के तहत इन लोगों को हटाने का काम किया, बदनाम करने का काम किया इन

लोगों को, बसों के अंदर किसी ने ये नहीं कहा कि बस के अंदर, हम कहते हैं कि 20 नवम्बर, 2019 को एक मार्शल थे अरूण कुमार उन्होंने चार साल की बच्ची का अपहरण हो रहा था उन्होंने उसके अपहरण होने को रोका, उसको बचाया, उस बच्ची की जान को बचाया। उसके बाद नवम्बर, 2019 में ही एक मार्शल थे संतोष कुमार जो डीटीसी बस के अंदर थे उन्होंने बस में से फोन चोरी होने से पकड़ा, उसको बचाया। कभी भाजपा के किसी नेता ने आज तक उनकी विडियो कभी वायरल करी, नहीं की। वो विडियो वायरल करते है देखो जी डीसीडी वाले हैं ये कितनी बदमाशी करते हैं ये कितनी गुंडागर्दी करते हैं। अपने भाजपा के कार्यकर्ताओं को वर्दी पहना देते थे और उनको बदनाम करने का काम करते थे। अरे ये मानसिकता छोड़ दो। तो इन लोगों को लैफ्टिनेंट गर्वनर ने जो हटाया है वो भाजपा के कहने पर हटाया है, साजिश के तहत हटाया है और मैं उनको कहना चाहता हूं कान खोलकर कि मैं फिर कहना चाहता हूं सदन के अंदर कि आप ये जो 10 हज़ार लोग हैं ना ये 10 हज़ार लोग नहीं है एक के साथ 100-100 लोगों का परिवार जुड़ा हुआ है अगर इनकी नौकरी बहाली नहीं की ना तो भारतीय जनता पार्टी के लोगो तुम्हें नानी याद दिला देंगे दौबारा ये 2024 के जो लोकसभा चुनाव के अंदर।

माननीया अध्यक्षः चलिये बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री कुलदीप कुमारः तो मुझे आपने बोलने का मौका दिया उसके लिये मैं आपका धन्यवाद करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं बहुत-बहुत धन्यवाद और इनकी नौकरी बहाली हो, इनका वेतन मिलें, ये अपने घर

में परिवार में खुशियों से वापस लौटें, मैं उसी के साथ अपना धन्यवाद करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं थैंक्यू।

माननीया अध्यक्षः ऋतुराज झा जी।

श्री ऋतुराज गोविंदः धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का मौका दिया। नेशनल क्राइम ब्यूरो का जो रिपोर्ट है मैडम वो कहता है कि Delhi is the most unsafe place for a woman और ये बहुत ही शर्म की बात है कि दिल्ली देश की राजधानी है और NCRB की रिपोर्ट कहती है कि दिल्ली जो है वो महिलाओं के लिये सबसे ज्यादा अन्सेफ है। जिस दिल्ली में प्रधानमंत्री रहते हैं, गृहमंत्री रहते हैं, लैफ्टिनेंट गर्वनर रहते हैं इतनी बड़ी दिल्ली पुलिस है जिसमें इतने सारी फोर्सिस है उसके बाद भी और ये कोई एक साल का रिपोर्ट नहीं ये जो है सो साल दर साल का रिपोर्ट है। अगर उठा कर देखेंगे तो उसमें कुछ बदल नहीं रहा है वो स्थिति और worst से worst होती जा रही है, क्यों? क्योंकि दिल्ली जो है वो घटिया राजनीति का शिकार हो गया है। कुछ दिनों पहले भी मैंने कहा था इस सदन में कहा था जैसे ठंडा मतलब कोको कोला होता है ऐसे गंदी राजनीति मतलब भारतीय जनता पार्टी। वो कैसे होती है? जब हमारी सरकार बनी, दिल्ली के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी की सरकार बनी, केजरीवाल जी की सरकार बनी, तो उस वक्त महिला सुरक्षा एक बहुत बड़ा मुद्दा था और माननीय मुख्यमंत्री जी ने थ्री लेयर सिक्योरिटी की एक तरह से एश्योरेंस दिया था दिल्ली की जनता को कि अगर बसें होंगी बस यानि की पब्लिक ट्रांसपोर्ट जहां पर महिलायें उस समय में

थोड़ी कतरातीं थीं क्योंकि वो अनसेफ फील करती थीं। तो उनको ये एश्योरेंस दिया गया उनको एक सेफ फील कराया गया उनको एक sense of security दी गई कि आपको हम थ्री लेयर सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे whether it is a panic button, CCTV camera and bus marshals उसका नतीजा क्या हुआ सोचिये, बस मार्शल्स की जब नियुक्ति हुई महिला सुरक्षा को ध्यान में रखते हुये बसिज़ के अंदर और सीसीटीवी कैमरे लगाये गये, पैनिक बटन्स लगाये गये, तो महिला commuters की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ गई और जब फ्री बसिज़ कर दी गईं तो उससेक्या हुआ कि महिलाओं का वकर्फोर्स बहुत ज्यादा बढ़ा क्योंकि दिल्ली के अंदर में जगह-जगह, दूर-दूर तक महिलायें जाने लग गईं काम की तलाश में, उनका कन्ट्रिब्यूशन एक तरह से बहुत ज्यादा बढ़ गया और हम सबने देखा है कि किस तरीके से महिलायें सेफ फील करती थीं। सीसीटीवी कैमरा है, अच्छी बात है लेकिन जब कोई फिज़िकली बस के अंदर में कोई मार्शल अगर मान लीजिये वर्दी में खड़ा है एक महिला को sense of security feel होती थी कि आई एम सेफ। कुछ अगर भूल-चूक हो जायेगी तो कोई मेरा है, कोई मेरा भाई है, कोई मेरा बेटा है जो मेरी मदद करेगा तो इतना अच्छा वो था। इन्होंने क्या किया टैक्निकल बातें मदन लाल जी ने बहुत बताई कि किस साल में क्या हुआ, नहीं हुआ, फाइलें कैसे चलीं मैं थोड़ा सा इसका वो बताना आपको चाहता हूं कि 2015 से लेकर के 2022 तक 7 साल तक सब कुछ लीगल था, इनको तनख्वाह भी मिल रही थी, ये ड्यूटी भी कर रहे थे, सब लोग जो है सो ड्यूटी पर जा भी रहे थे, सब कुछ अच्छा

चल रहा था और 2022 में सब कुछ इलिगल हो गया। सरकार का काम होता है कोई अगर पेंच है, कोई लीगल पेंच है, कोई टैक्निकल पेंच है तो उसका समाधान निकाले, कोई ऐसी समस्या नहीं है जिसका समाधान सरकार के पास ना हो, हर समस्या का समाधान है। हो क्यों नहीं पा रहा है क्योंकि जान-बुझकर के ये 10 हज़ार से ज्यादा जो लड़के-लड़कियां हैं सब गरीब परिवार से आते हैं, प्रवासी लोग हैं, कच्ची कॉलोनी में रहते हैं, झुग्गी-बस्ती में रहते हैं लेकिन अपना ईमानदारी से काम करके अपना परिवार को पालते हैं, ईमानदारी से करते हैं इन सबका रोजगार छीनने का काम भारतीय जनता पार्टी के लैफ्टिनेंट गर्वनर ने किया, गंदी राजनीति के तहत किया और ऊपर से इनको भड़काते हैं, इनको हमारी सरकार के खिलाफ भड़काते हैं, हमारे नेता के खिलाफ भड़काते हैं। अभी चार महीने से जब इनको ड्यूटी करना चाहिये, अपना परिवार पालना चाहिये। मैं एक-एक परिवार को जानता हूं किराड़ी के कम से कम पांच सौ से ज्यादा मेरे खुद के क्षेत्र के पांच सौ से ज्यादा लड़के-लड़कियों सिविल डिफेंस के माध्यम से उनको रोज़गार मिला। वो बच्चे हैं क्या? कोई जो ऐसा हो जो अपने परिवार को चलाता है, कोई जो है सो किसी के माता-पिता नहीं है अपने परिवार पर अकेला एक अकेला व्यक्ति जो है पूरे परिवार को चला रहा था। इन सारे गरीब बच्चों के साथ में अन्याय करने का काम किया है इन्होंने। सबका रोज़गार छीन लिया, ये नियम वो नियम अरे मंत्रीजी ने कह दिया कि भईया अगर cabinet में ही लाना है तो कैबिनेट में ले आओ, पास हो जायेगा। कैबिनेट में लायेंगे भी नहीं, सरकार को बदनाम

भी करेंगे, इनको नौकरी पर बहाल भी नहीं करेंगे, इनकी तनख्वाह भी नहीं देंगे, बोलते होम गार्ड लगायेंगे। अरे होम गार्ड लगाओगे तो इन्हीं को होमगार्ड में लगा दो, अल्टिमेट्ली इनका रोज़गार भी नहीं जायेगा और महिलायें सुरक्षित भी महसूस करेंगी। आज क्या हुआ? आज ये सब गंदी राजनीति के चलते बसें जो हैं वो मार्शल्स फ्री हो गईं। अब कहते हैं कि अगर पैनिक बटन है, सीसीटीवी कैमरा है तो मार्शल्स की क्या जरूरत है। अरे ये कौन सी बात हुई। आप मुझे बताईये कि अगर सीसीटीवी कैमरा की बात करें तो दिल्ली में तो पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा सीसीटीवी कैमरा है कल को कहेंगे दिल्ली पुलिस की क्या जरूरत है सब कुछ सीसीटीवी कैमरा ही कर देगा। अरे सीसीटीवी कैमरे का अपना रोल है, मार्शल्स का अपना रोल है, सबकी अपनी जिम्मेदारी है। आज इन गरीब बच्चों को जो कि गरीब परिवार से आते हैं मार्शल्स के रूप में नौकरी कर रहे थे अपना परिवार पाल रहे थे, महिलाओं की सुरक्षा कर रहे थे, देश के अंदर कॉन्ट्रिब्यूशन कर रहे थे, हमारी इकॉनॉमी में, समाज में कॉन्ट्रिब्यूशन कर रहे थे, सबको इन्होंने सड़क पर बिठा दिया, धरने पर बिठा दिया और ऊपर से इनको उकसाते हैं, गंदी राजनीति करते हैं। हम आपके माध्यम से एक ही बात कहना चाहते हैं मैडम स्पीकर कि जल्दी से जल्दी इन सभी गरीब परिवार से आने वाले बच्चे-बच्चियों को जोकि मार्शल्स के रूप में ड्यूटी कर रहे थे इनको दौबारा से बहाल किया जाये ताकि ये अपनी ड्यूटी कर सकें, अपना परिवार चला सकें, सेवा कर सकें और ये गंदी राजनीति बंद हो, जो भी समाधान करने की जरूरत है उसको किया जाये, लैफ्टिनेंट गर्वनर ये गंदी राजनीति करना बंद करें ये मैं कहना चाहता हूं।

माननीया अध्यक्षः चलिये, बहुत-बहुत धन्यवाद, महेंद्र गोयल जी, वक्ता बहुत ज्यादा हैं समय सीमा का ध्यान रखें आप लोग।

श्री महेंद्र गोयलः पूरा ध्यान रखा जायेगा जी धन्यवाद आपका। मैं आपका शुक्रिया करता हूं कि आपने मुझे इस महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का मौका दिया जो मदन लाल जी लेकर आये। इस समय मैं कैमरे वालों से कहूंगा उस गैलरी की तरफ भी एक बार कैमरा अपना घुमा दें जो वो बस मार्शल बैठे हैं वहां पर। आप लोगों की आवाज़ इस सदन के अंदर उठ रही है और ये सरकार पहले भी आपकी नौकरी दी थी आज भी आपको नौकरी दिलवाने के लिये यहां पर इस सदन के अंदर प्रस्ताव लेकर आई है, तय आप लोगों को करना है कि आप लोगों को क्या करना है। आप लोगों की मंशा के ऊपर हमें कहीं पर शक नहीं है। ये ठीक है कि विपक्षी पार्टी वाले कहते हैं कि ये केजरीवाल की पुलिस है, ये केजरीवाल की फोर्स है। मैं इस सदन के माध्यम से कहता हूं यदि नेता विपक्ष के अंदर दम था हालांकि बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, पार्टी का दवाब है, गंदी राजनीति का वो भी शिकार है क्योंकि ऐसी पार्टी ने तानाशाही मचा रखी है कि जिन लोगों को दिल्ली सरकार रोज़गार देती है तो उन लोगों का रोज़गार मिटाया जाये ऐसी घटिया राजनीति इन केन्द्र सरकार वालों ने कर रखी है। मैं उनको कहता हूं:

‘वक्त से दिन और रात,
वक्त से कल और आज,
वक्त की हर शह गुलाम,

वक्त का हर शह पर राज,
आदमी को चाहिये
उन तानाशाहियों को बोल रहा हूं
आदमी को चाहिये वक्त से डर कर रहे
ना जाने कौन घड़ी वक्त का बदले मिजाज़'

ये वक्त है आपकी लगातार दो बार सरकार बनाई है केन्द्र के अंदर लेकिन जिस तानाशाही रवैये के ऊपर आये हैं वो बहुत घटियापन होगा। इन लोगों के रोज़गार के साथ में मत खेलें, ये सिर्फ 10 हज़ार आदमी नहीं हैं, 10 हज़ार परिवारों का ये एक समूह है उसके साथ में इनके रिश्ते भी होते हैं वो रिश्तेदार भी हैं। आप लोगों से कहता हूं, आज इस सदन की कार्यवाही को आप वायरल करना, इस सदन की कार्यवाही को पूरी की पूरी दिखाना कि एक तरफ से केजरीवाल लगा हुआ है आप लोगों को रोज़गार देने के लिये, आप लोगों को रोज़गार दिलवाया था। 2015 से लेकर 2022 तक तो ये पॉलिसी बहुत अच्छी थी जिस समय अरविंद केजरीवाल लेकर आया है एक भी दुर्घटना नहीं घटी, एक भी बहन–बेटी के साथ में कहीं पर किसी ने साहस नहीं किया, किसी बहन–बेटी के साथ में छेड़खानी नहीं हुआ। मैं सैल्यूट करता हूं इन बस मार्शलों को, सिविल डिफेंस के सभी वॉलियन्टर्स को कि आप लोगों ने अपनी ड्यूटी को बहुत मुस्तेदी के साथ में निभाया है, तो परमात्मा भी देख रहा है आपको नौकरी मिलकर रहेगी ये सदन आप लोगों को आश्वासन दे रहा है क्योंकि केजरीवाल जो ठान लेता है उसको पूरा भी करता है। केजरीवाल के ये जितने भी सिपाही बैठे हैं

यहां पर आप लोगों के लिये चर्चा कर रहे हैं और आप लोगों को नौकरी दिलवाने के लिये हमें यदि अंतिम सांस तक भी लड़ना पड़ेगा तो हम लड़कर रहेंगे। जब 2015 से लेकर 2022 तक ये पॉलिसी ठीक थी, उस समय भी दिल्ली के अंदर चीफ सेक्रेटरी होते थे, सेक्रेटरी होते थे, फाइनांस सेक्रेटरी होते थे, यदि इस पॉलिसी के अंदर खामी थी तो उस समय के मौजूदा प्रिसींपल सेक्रेटरियों के ऊपर भी, चीफ सेक्रेटरी के ऊपर भी और उन सभी सेक्रेटरियों के ऊपर भी वो कार्यवाही होनी चाहिये। इन लोगों का कसूर क्या था? इन्होंने सेवाएं दे रखी थी। तो जिस प्रकार से ये गंदी राजनीति हो रही है, ये गंदी राजनीति नहीं होनी चाहिए। मदनलाल भाई जो प्रस्ताव आप लेकर आये हैं आपको सैल्यूट करता हूं और ये सदन पूरा का पूरा सदन एकजुट है। नेता, विपक्ष बड़ी खूबसूरती के साथ कभी कुछ बोल रहे हैं, कभी कुछ बोल रहे हैं। अरे ये सदन तो गेस्ट टीचर के लिए भी बिल लेकर आया था कि उनको पक्का कर दिया जाये। वो अपनी सेवाएं दे रहे है। दिल्ली के अंदर मैं बहुत खास तौर पर कहता हूं, यदि हमारी सरकार बनाने के अंदर सबसे ज्यादा बड़ा हाथ रहा है तो शिक्षा के अंदर जितने भी टीचर लगे हुए हैं, उन लोगों का रहा है। हॉस्पिटलों के अंदर जितने भी डॉक्टर्स लगे हुए हैं, उनका रहा है। शिक्षा और चिकित्सा के नाम के ऊपर ये तीन-तीन बार सरकार बनाने का काम किया है। मैं सभी गैस्ट टीचर के लिए भी वो कहता हूं कि जिस प्रकार से हमारी फाइल गई थी, अरविंद केजरीवाल ने जिस फाइल को भेजा था उसको वो पास करे और इन लोगों के लिए भी अरविंद केजरीवाल जी लगे हुए है, पूरे का

पूरा सदन लगा हुआ है। मैं इस सदन के माध्यम से एलजी साहब से ये दरख्वास्त करता हूं, एलजी साहब अच्छे और बुरे की पहचान होती है। आप बुराई के मोह में मत चढ़ो, इन लोगों की बद्दुआ को मत लो। पता नहीं किस गरीब की हाय कब खा जाए। आपके साथ में कब क्या नुकसान हो जाए। आज आपको लगता है कि आपके वो पैरोकार बैठे हैं और मैं अरविंद केजरीवाल जी की सोच को एक और सैल्यूट करता हूं कि इस सदन के साथियों को उन्होंने संसद के अंदर भी सिर्फ इस लिए भेजने का काम किया है कि वो दिल्ली के दर्द को जानते हैं और मैं उन सभी साथियों को शुभकामनाएं देता हूं कि वो लोग यहां से दिल्ली से चुन कर जायेंगे और दिल्ली की आवाज को संसद के अंदर भी बुलंद करेंगे। आप लोगों के हक के लिए आज दिल्ली विधान के अंदर लड़ रहे हैं और कल आने वाले वक्त के अंदर दिल्ली के साथ में कहीं पर अन्याय होगा, आप लोगों की नौकरी के साथ में कहीं पर अन्याय होगा तो उस सदन के अंदर भी लडेंगे, पार्लियामेंट कें अंदर भी लड़ेंगे।

माननीया अध्यक्षः चलिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री महेन्द्र गोयलः ये काम हम लोग करेंगे।

माननीया अध्यक्षः बहुत-बहुत धन्यवाद। अखिलेशपति त्रिपाठी जी।

श्री महेन्द्र गोयलः बस एक बात कहता हूं।

'नजर को बदलो तो नजारे बदल जायेंगे
और सोच को बदलो, तो सितारे बदल जायेंगे,

किस्ती को बदलने की जरूरत नहीं मेरे साथियो
बस उसका रूख बदल तो किनारे बदल जायेंगे,
किनारे बदल जायेंगे।'

आज जो साथी हमारे इस सदन का हिस्सा है और आने वाले समय के अंदर वो पार्लियामेंट का हिस्सा हो ऐसी मैं शुभकामनाएं देता हूं। जय हिन्द। जय भारत। घबराने की जरूरत नहीं। अरविंद केजरीवाल आपके लोगों के साथ में है आपका बिल पास होकर रहेगा। ये हम लोग कहते हैं। धन्यवाद।

माननीया अध्यक्षः अखिलेशपति त्रिपाठी जी।

श्री अखिलेशपति त्रिपाठीः धन्यवाद अध्यक्षा महोदया। अभी विपक्ष के नेता घड़ियाली आंसू रोते हुए बाहर चले गए क्योंकि वो जो है उनको सिविल डिफेंस के जो हमारे वॉलेंटियर्स जो पूरा देश जिस समय आपदा में जूझ रहा था, दिल्ली भी जूझ रही थी, कोविड के दौरान। मुझे याद है वो समय बड़े-बड़े लोगों का काम करने का जज्बा टूट रहा था। सभी लोग चाहते थे कि अपने घरों तक सिमट जायें। सभी लोग चाहते थे कि कहीं मैं बाहर ना जॉऊ और कोई बीमारी ना लग जाये। सभी के परिवार वाले एक दूसरे को सलाह देते थे। उस समय दिल्ली में ये सिविल डिफेंस के वॉलेटियर्स ने ना केवल अस्पतालों में, दिल्ली की सड़कों पर, उन जगहों पर जहां पर ये कहा गया कि बहुत ज्यादा कोविड फैला हुआ है, ये विशेष जोन बनाया गया है जहां पर, जहां जाना आना restricted था, वहां पर भी डयूटी करने का काम किया

इन लोगों ने। स्पीकर महोदया, मैं तो सोचता था कि ऐसे निडर सिपाहियों को ऐसे आपातकाल में काम करने के बदले में सर्विसेज विभाग क्योंकि एलजी साहब के पास है, अलोकतांत्रिक तरीके से उनको इनाम मिलेगा हम सोचते थे। अभी तक ये ही रहा परम्परा कि जो काम करता है उसको पारितोषिक मिलता है। आज मैं पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के लोगों से, एलजी साहब से पूछना चाहता हूं कि इन कर्मचारियों ने क्या गलती कर दिया? कोविड में डयूटी करके अपनी जान की बाजी लगा करके दिल्ली को बचाने का काम करके सरकार का साथ दे करके क्या गलती कर दिया? इनको पीड़ा इस बात की नहीं थी, पीड़ा इस बात की है कि जब अरविंद केजरीवाल सरकार खड़ी होती है कहीं पर तो जब रोजगार का आंकड़ा देने की बात होती है तो एक लम्बा फेहरिस्त नजर आता है, वो इनको पीड़ा होती है भारतीय जनता पार्टी के लोगों को। ये उस रोजगार की फेहरिस्त को कम करना चाहते थे। दिल्ली के युवाओं की हत्यारी जो केन्द्र की सरकार बैठी हुई है, एलजी के माध्यम से इन युवाओं की हत्या करना चाहती है। हमारी सरकार केवल सिविल डिफेंस कर्मचारियों को ही नहीं रोजगार देने का काम किये। अलग-अलग जगह पर कॉन्ट्रेक्ट पर भी बहुत सारे लोग लगे हुए थे, उनको भी निकालने का काम एलजी के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी ने पिछले दरवाजे से करने का काम किया है। जल बोर्ड में बहुत सारे टेंकर पर बच्चे काम करते थे उनको निकालने का काम हुआ। पीडब्ल्यूडी में बहुत सारे बच्चे काम करते थे कॉन्ट्रेक्ट पर उनको निकालने का काम हुआ। अलग-अलग एसडीएम ऑफिस में

सिविल डिफेंस के कर्मचारी काम करते थे, उनको निकालने का काम हुआ। अलग-अलग ट्रांसपोर्ट के दफ्तरों में काम करते थे तो उनको निकालने का काम हुआ। जहां भी कर्मचारी नहीं थे वहां पर सिविल डिफेंस के कर्मचारी जाकर काम करते थे और सरकार का काम सुचारू रूप से चलता था। यानि कि इन सिविल डिफेंस के कर्मचारियों को निकालने के पीछे एलजी की एक ही मंशा था कि सरकार को पंगू बना दिया जाए और काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या कम कर दी जाये। लेकिन याद रखियेगा, यह अरविंद केजरीवाल जी की सरकार है, अगर इनको हक और हक-हुक की लड़ाई लडकर रोजगार देना जानते हैं अरविंद केजरीवाल जी, तो इनको फिर से उनका जो हक है वो देने के लिए लड़ने के लिए पीछे नहीं रहेंगे। अध्यक्षा महोदया, अभी ये कह रहे थे कि आंगनवाड़ी के लोगों को, जब हमारी सरकार ने आंगनवाडी के लोगों का तनख्वाह बढ़ाया तो ये भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, आठ-दस महीने तक उन कर्मचारियों की तरख्वाह की जो फाइल थी वो भी इनके एलजी साहब पास करने से रोके हुए पड़े थे। घडियाली आंसू रो रहे हैं ये लोग। एससी, एसटी, ओबीसी के मामले को उठाया राजेन्द्र जी ने। भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में एलजी के माध्यम से उनके रोजगार को मारने का काम कर रही है। अध्यक्षा महोदया मैं आज सिविल डिफेंस के एक-एक सिपाही के साथ खड़ा हूं। हमारी सरकार, अरविंद केजरीवाल जी की सरकार, हमारे मुख्यमंत्री जी, पूरा केबिनेट सिविल डिफेंस के एक-एक कर्मचारियों के साथ खड़ा है। आपके योगदान की हम प्रशंसा करते है जो आपने कोविड में काम

किया है। उसका कोई मोल नही है। थोड़ा सा भी अगर शर्म, थोडा सा भी अगर इनके आंखों में मानवता होगा, हृदय में मानवता होगा अगर एलजी साहब के, भारतीय जनता पार्टी के लोगों के, तो इनकी आवाज को सुनेंगे और इनको पक्का करने का काम करेंगे। आप चाहते हैं होम गार्ड की भर्ती करना तो होम गार्ड में कर दीजिए। लेकिन ये कहां कि परिपाटी है, होम गार्ड में भर्ती करेंगे नहीं, जो लोग बसों में महिलाओं की सुरक्षा का काम कर रहे हैं उनको निकाल कर बाहर कर देंगे। ये कौन सी परिपाटी लेकर आये हैं।

माननीया अध्यक्षः बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अखिलेशपति त्रिपाटीः ना केवल ये युवाओं के दुश्मन हैं बल्कि महिलाओं की सुरक्षा के दुश्मन है। आज दिल्ली की महिलायें सुन रही है, आपकी सुरक्षा के लिए सिविल डिफेंस के कर्मचारियों को बसों में लगाया गया था, इनको निकालने का काम भारतीय जनता पार्टी के एलजी ने किया है। आप लोग आने वाले लोक सभा के चुनाव में ध्यान रखना इन लोगों का क्या हालत करना है। पुनः मैं इनकी बहाली की मांग करते हुए इनका जायज हक का समर्थन करता हूं और मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं कि वो हमेशा अपने सिविल डिफेंस के कर्मचारियों के साथ खड़े रहे हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद।

माननीया अध्यक्षः संजीव झा जी। समय का ध्यान रखें।

श्री संजीव झाः बहुत-बहुत धन्यवाद अध्यक्ष महोदया। फिलहाल तो सिविल डिफेंस वॉलेंटियर्स का ध्यान रखना है। उसमें समय थोड़ा

बहुत ज्यादा लग जाए, इनकी पीड़ा बहुत बड़ी है। मुझे ये लगता है जो कुलदीप भाई मैंशन कर रहे थे कि 2012 में निर्भया की घटना हुई और वो दिल्ली में चलती हुई बस में हुई। उस आन्दोलन में हम लोग पूरी दिल्ली में खूब लाठी डंडे भी खाये, खूब आंसू गैस भी झेले। तब लगा कि अगर बस में कोई सिक्यूरिटी होता तो शायद इतनी बड़ी घटना नहीं होती। आज हमारे ओपोजिशन के जो नेता है, लीडर ऑफ ओपोजिशन हैं उन्होंने ना केवल सदन से बल्कि सभी सिविल डिफेंस वॉलेंटियर्स से भी वादा खिलाफी किया है। इसी सदन में उन्होंने कहा था कि आप ये प्रस्ताव को लेकर आइये और इस प्रस्ताव के साथ मैं खड़ा हूं और जहां-जहां जाने की जरूरत है मैं वहां-वहां जाऊंगा। लेकिन आज जब चर्चा हो रही है तो चर्चा को छोड़कर वो भाग गए। ये बड़ा ही शर्मनाक भी है और निंदनीय भी है। जैसा कि हमारे बाकी साथियों ने कहा कि इस पूरी चर्चा को सिविल डिफेंस वॉलेंटियर्स सदन में भी दर्शक दीर्घा में बैठकर देख रहे हैं और मुझे लगता है ये चर्चा बाहर भी देखी जा रही है। तो आप जो झूठ फैलाने की कोशिश कर रहे थे वो झूठ आपकी चलेगी नहीं। तीसरी बात कि वो कह कर गए कि बाकी कर्मचारियों को भी पक्का करो, हम तो तैयार हैं। इसी सदन में राजेन्द्र पाल गौतम ने ही प्रस्ताव लाया है उस पर भी चर्चा करेंगे। भागने तो आपको हम देंगे नहीं । आप जो ये भागने का तरीका निकाल रहे हैं वो भागने का तरीका इस्तेमाल नहीं करना, चर्चा उस पर भी होगी। लेकिन आज सिविल डिफेंस पर चर्चा इसलिए हो रही है कि लगातार तीन महीने से धरने पर बैठे हुए हैं लोग। उनके पास अब कोई चारा

नहीं दिख रहा है। वो जायें तो जायें कहां। वो कभी यहां भाग रहे हैं, कभी वहां भाग रहे हैं। तो ये अलग से चर्चा सिविल डिफेंस वॉलेंटियर की केवल इसलिए हो रही है, चूंकि ये दस हजार वो परिवार जिसका ये रोजी रोटी का आसरा था वो रोजी रोटी छिन गया है। हालांकि केन्द्र सरकार से क्या ही उम्मीद किया जाए। वो तो जो आर्मी में जो बहाली होती थी उसको भी चार साल का अग्निवीर योजना करके कर दिया। वो किसी ने बड़ा अच्छा कहा कि रामचन्द्र जी कह गए सिया से ऐसा मोदी युग आयेगा, बाप करेगा नौकरी, बेटा रिटायर हो जायेगा। तो ये तो ऐसी योजना लेकर आ रहे हैं कि बाप की नौकरी करते-करते बेटा रिटायर हो जाता है, ये मोदी युग में ही हो सकता है। तो उनसे बहुत उम्मीदें नहीं हैं। लेकिन दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी की सरकार दिल्ली के हर एक अन्तिम व्यक्ति की चिंता करती है। आज ये जो दस हजार परिवार हैं बिल्कुल ठीक ऋतुराज भाई ने कहा ये सब कच्ची कॉलोनी में रहने वाले लोग हैं। मेरी अपनी constituency में हजार से ज्यादा वॉलेंटियर सिविल डिफेंस वॉलेंडियर हैं और वो सिविल वॉलेंटियर उनकी कई लोग जो मेरे ऑफिस में आते हैं जब अपनी-अपनी बातें बताते है, तो आंखों में आंसू आ जाते हैं कि उनका एक लड़का आया उसके पिता जी को कैंसर है। दो छोटे-छोटे बच्चे हैं। पांच महीने से वो नौकरी पर नही है। उसका घर कैसे चलेगा? अब वो अपने पिता जी का इलाज नहीं करा पा रहा, अपने घर की रोजी रोटी नहीं चला पा रहा। वो कह रहा था कि मेरे पास सुसाइड के सिवाय दूसरा और कोई रास्ता नहीं है। इसी तरह से रोज जो कहानी, चूंकि सब गरीब बच्चे हैं,

गरीब लोग है। ये गरीब परिवार से आते हैं सब। कई लोग किराये पर रह रहे हैं। कोई दो हजार, तीन हजार, चार हजार ये किराये पर रह रहा है। ऐसे लोगों की नौकरी छीनेंगे एलजी साहब तो आपको हाय लगेगी। इनकी बद्दुआएं लेकर जाओगे कहां तुम। कैसी राजनीति कर रहे हो तुम लोग। अरे एलजी आज हो, कल रहोगे? कुछ ऐसा कर जाओ जिससे दुआएं मिलें आपको। बद्दुआएं ले रहे हो आप। जैसा कि बाकी साथियों ने कहा 2022 से सब कुछ ठीक-ठाक चल रहा था। 2022 के बाद ऐसा क्या हो गया कि सब कुछ इल्लिगल हो गया। भई फाईनांस डिपार्टमेंट ने, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने कहा है, प्रपोजल दिया कहा कि भई दो महीने से सैलेरी नहीं आ रही है, सेलेरी के पैसे दो और ज्यों ही ये फाइल गई तो फाईनांस डिपार्टमेंट कहता है कि भई ये इलिगल है, illegality है इसमें। भई ये केबिनेट का सैंक्शन नहीं लिया 2015 में। तो फिर जो अभी बाकी साथियों ने कहा, गोयल साहब ने कहा कि अगर फिर ये illegality है तो फिर वो सभी सैक्रेट्री जिम्मेदार हैं, उन पर सब पर कार्रवाई करो। इस सिविल डिफेंस पर कार्रवाई क्यों कर रहे हो, बच्चों पर कार्रवाई क्यों कर रहे हो आप? क्यों नहीं कार्रवाई कर रहे उन सभी सैक्रेट्री पर जिसके समय में ये पैसे गए? फिर तो उनकी नौकरी जानी चाहिए थी, इलिगल काम हो गया। आप कह रहे हो कि केबिनेट नहीं हुआ। तो केबिनेट कोई, सरकार तो तैयार है, सरकार तो कह रही है। क्यूं नहीं केबिनेट में ला रहे हो आप? प्रपोजल भी बना।

माननीया अध्यक्षः कम्पलीट कीजिए।

श्री संजीव झाः तो मुझे ये लगता है कि आज भारतीय जनता पार्टी के कहने पर जो दिल्ली की इस सिविल डिफेंस वॉलेंटियर्स के साथ जो बदला ले रहे हैं ये बिल्कुल ठीक नहीं है। एलजी साहब को तो कम से कम ऐसा नहीं करना चाहिए। एक बात बताइये आप कि ये ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर के क्लीयर डायरेक्शन के बावजूद आप केबिनेट में नहीं ला रहे हो। ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर, रेवेन्यू मिनिस्टर्स की मिटिंग हुई उसके बाद भी नहीं ला रहे हो। ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर ने written सीएम साहब को apprise किया। सीएम साहब के कहने के बावजूद भी नहीं ला रहे हो आप। ये सरकार कैसे चलेगी? अगर Transaction of Business Rule में मिनिस्टर का ऑर्डर सैक्रेट्री पर बाईंडिंग है और सैक्रेट्री नहीं मान रहा। कहां जायेगा? मैं आज सदन के माध्यम से माननीय सुप्रीम कोर्ट को भी कहना चाहता हूं कि अब आप ही एक आसरा हैं। सारे organs सारी मशीनरी फेल हो चुकी है। अगर ये फैसला नहीं हुआ तो दिल्ली की जनता पर आफत आ जायेगी। चुनी हुई सरकार के पावर को खत्म किया जा रहा है। मैं इस सदन को एक बात और कहना चाहता हूं। ये सदन एलजी के सैक्रेट्रिएट को सेलेरी देता है लेकिन एलजी का सचिवालय दिल्ली की जनता के काम को रोकता है। कि ये सदन एलजी सचिवालय को सेलेरी को रोक दिया जाये, नहीं दिया जाये?

माननीया अध्यक्षः चलिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री संजीव झाः तो मैं आपके माध्यम से अध्यक्षा महोदया तीन निवेदन करना चाहता हूं। पहली बात कि ये सिविल डिफेंस के जो

वॉलेंटियर हैं हमारे सारे साथियों ने बताया कि किस तरह से ये दिल्ली के लोगों की सेवा कर रहे थे। तो अगर ये अभी राजेन्द्र पाल गौतम से बात भी हो रही थी कि निष्काम सेवा की बात भी है भई ये 270 मेरे ख्याल से clause है Industrial dispute act में कि 240 डेज या 240 डेज काम करते हैं Industrial dispute act तहत के इनको भी रेगूलर कर दिया जाए। ये रेगूलर हो जायें। दूसरी बात कि ये जो केबिनेट के लिए फाइल बना था ये मिनिस्टर के पास सैक्रेट्री immediately भेजे। तीसरी बात कि अगर इस फाइल को केबिनेट अप्रूवल के लिए नहीं भेजा गया तो फिर ये दस हजार सिविल डिफेंस वॉलेंटियर भी और हम सब लोग एल जी साहब को छोड़ेंगे नहीं।

माननीया अध्यक्षः चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।

श्री संजीव झाः और एक अन्तिम बात। मैं इस सदन के माध्यम से सभी सिविल डिफेंस वॉलेंटियर्स को रेक्वेस्ट करना चाहता हूं आप तीन महीने से धरने पर बैठे हुए हैं आप धरना खत्म कीजिए, हम आपके साथ है। आपकी लड़ाई हम लोग मिलकर लडेंगे। सदन के साथी मिलकर लडेंगे। लेकिन आपके साथ-साथ चलेंगे और जहां-जहां चाहे कोई ऑफिसर हो, चाहे वो एलजी हो, जो फाइल को रोकेगा उसको हम छोडेंगे नहीं। बहुत-बहुत धन्यवाद।

माननीया अध्यक्षः माननीय मंत्री आतिशी जी।

माननीया राजस्व मंत्री (श्रीमती आतिशी): धन्यवाद अध्यक्ष महोदया। अध्यक्ष महोदया आज मैं सिर्फ एक विधायक होने के नाते

नहीं, एक मंत्री होने के नाते नहीं बल्कि दिल्ली में पैदा हुई, दिल्ली में पढ़ी लिखी, दिल्ली में काम की एक महिला होने के नाते से भी बोल रही हूं। यहां पर हमारे सिविल डिफेंस के कई साथी भी मौजूद हैं। हमारे विधायक साथी भी मौजूद हैं। बहुत सारे ऑफिसर भी मौजूद हैं। मैं आज इन सब को बताना चाहती हूं कि आज से नहीं दशकों से दिल्ली की बसों में दिल्ली की डीटीसी बसों में महिलाओं का क्या एक्सपीरियंस होता है। चाहे एक बच्ची हो जो स्कूल जा रही हो डी. टी. सी. बस के माध्यम से, चाहे एक कॉलेज में पढ़ने वाली लड़की हो जो कॉलेज जा रही हो, चाहे एक कामकाजी महिला हो, एक महिला के लिए दिल्ली में दशकों से डीटीसी में सफर करना किसी महाभारत से कम नहीं रहा। एक भरी हुई डीटीसी बस में वो चढ़ती हैं। वहां पर जो पुरूष है अलग-अलग उम्र के, भद्दे-भद्दे कॉमेंट्स करते हैं, गलत निगाह से देखते हैं, अशलील व्यवहार करते हैं। कोई भी महिला डीटीसी बस में सिर्फ मजबूरी के कारण जाती थी। जिसकी स्कूल की बस नहीं होती थी, जिसका कॉलेज घर से दूर होता था। माता-पिता भी ये कहते थे कि दूर के कॉलेज में मत एडमिशन लो किस तरह का दुर्व्यवहार बसेज में होता है। मैं तो अपने आप को fortunate मानती हूं, लक्की मानती हूं कि मैंने जिस स्कूल से पढ़ाई की हमारी स्कूल की अपनी बस होती थी। मैने जिस कॉलेज से पढ़ाई की वो मेरे घर के पास होता था, तो पैदल जाती थी कॉलेज। लेकिन दिल्ली की ज्यादातर महिलाएं, दिल्ली की ज्यादातर लड़कियां इतनी fortunate नहीं होती। उन्हें डीटीसी बसों में स्कूल जाना पड़ता है। उन्हें डीटीसी बसों के

माध्यम कॉलेज पड़ता है। उन्हें डीटीसी बसों के माध्यम से फैक्ट्री में, ऑफिस में, दुकानों में काम करने के लिए जाना पड़ता है। अध्यक्ष महोदया, इतने सालों से दिल्ली की महिलाएं इस समस्या का सामना करती आई हैं। सरकारें आई सरकारें गई, पार्टियां आई, पार्टियां गई, लेकिन किसी ने भी दिल्ली की लड़कियों के बारे में, दिल्ली की महिलाओं के बारे में नहीं सोचा। अध्यक्ष महोदया, ये दिल्ली वालों का सौभाग्य है कि 2015 में दिल्ली के लोगों को अरविंद केजरीवाल जी जैसा मुख्यमंत्री मिला। ये दिल्ली की लड़कियों का, दिल्ली की महिलाओं का सौभाग्य है कि उन्हें एक ऐसा मुख्यमंत्री मिला जिन्होंने दिल्ली की सरकार को, दिल्ली के 2 करोड़ लोगों को अपने परिवार की तरह चलाया है। एक ऐसा मुख्यमंत्री मिला जो सिर्फ जिस तरह से अपने घर की बेटी, जिस तरह से अपनी बेटी अपनी बहन की चिन्ता करता है उस तरह से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल जी ने दिल्ली की हर लड़की की चिन्ता करी, हर महिला की चिन्ता करी। एक भाई के तौर पे, बड़े बेटे के तौर पे और वहीं से शुरूआत हुई इस बस मार्शल्स की योजना की। मैं कई ऐसे सोचती हूँ कि ये समस्या तो दशकों से चलती आ रही है, लेकिन 2015 में अरविंद केजरीवाल जी के मुख्यमंत्री बनने से पहले आज तक किसी ने समाधान के बारे में सोचा क्यों नहीं था। इतनी सिम्पल सी बात है कि अगर कोई व्यक्ति उस बस में मौजूद हो जहां पर एक महिला के साथ एक लड़की के साथ अश्लील व्यवहार हो रहा है तो वो वहीं पर उसी समय उस अश्लील व्यवहार को रोक सकता है, बस के माहौल को ठीक कर सकता है और मुझे

खुशी है इस बात की कि 2015 से ही जब से अरविन्द केजरीवाल जी दिल्ली के मुख्यमंत्री बने तब से इस बस मार्शल्स स्कीम को लागू किया गया। इसमें कई उतार-चढ़ाव आये कि जी होमगार्ड को रखना है, सिविल डिफेंस को रखना है। जी इतने होमगार्ड रखिए वो हम रिक्रूट नहीं कर पाये। सिविल डिफेंस को रखिए, आधे-आधे रखिए, लेकिन क्योंकि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल जी को दिल्ली की लड़कियों की, दिल्ली की महिलाओं की सुरक्षा की और सम्मान की चिन्ता थी। हर बार जब इस काम को रोकने की कोशिश हुई अरविन्द केजरीवाल जी ने इसका कोई समाधान निकाला कि दिल्ली की बसों में मार्शल बने रहें। ये स्कीम लगातार चलती रही। 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, जनवरी 2023 से कुछ अजब हुआ कि वो ही अफसर जिन्होंने स्कीम की शुरूआत करी, वो ही अफसर जो इसके लिए पैसा रिलीज करते आये हैं, वो ही अफसर जो महीने-दर-महीने बस मार्शल्स को, सिविल डिफेंस वॉलिंटियर्स को तनख्वाह देते आये हैं, वो ही अफसर जो इन सिविल डिफेंस वॉलिंटियर्स को बस मार्शल बनने के लिए रिक्रूट करते हुए आये हैं सालों से, वो ही अफसर फाइलों पे ऑब्जेक्शन लगवाने लग गए। कभी फाइनेंस डिपार्टमेंट ने सवाल उठाए। उन्होंने पूछा जी सिविल डिफेंस वॉलिंटियर्स को कैसे रख सकते हैं आप बस मार्शल्स के लिए। कभी रिवेन्यु डिपार्टमेंट ने जिन्होंने इन सिविल डिफेंस वॉलिंटियर्स को खुद रिक्रूट किया, खुद ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के पास भेजा, उन्होंने सवाल उठाए कि जी सिविल डिफेंस वॉलिंटियर्स को बस मार्शल्स के तौर पे कैसे रखा जा सकता है।

कभी ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने जो इतने सालों से उनको तन्ख्वाह देते हुए आ रहे हैं, कहने लगे, जी बस मार्शल की जरूरत भी है कि नहीं, बस में तो सीसीटीवी कैमरा लग ही गया, बस में तो पैनिक बटन लग ही गया। मैं उन सब अफसरों से कहना चाहूंगी कि आप तो खुद chauffeur driven गाड़ियों में चलते हैं। आपको अंदाजा नहीं है कि दिल्ली की लड़कियों को, दिल्ली की महिलाओं को किस तरह के दुर्व्यवहार का सामना करना पड़ता है। क्या करेगा सीसीटीवी कैमरा? सीसीटीवी कैमरा के माध्यम से कोई सुपरमैन कूद कर आ जायेगा क्या बस में उस व्यवहार को रोकने के लिए? सीसीटीवी कैमरा तो जब कोई जुर्म हो गया, जब कोई दुर्व्यवहार हो गया, फिर कोई एफआईआर करने जाए, पुलिस स्टेशन के धक्के खाये तब तो सीसीटीवी कैमरा की फुटेज मांगी जाती है। क्या सीसीटीवी कैमरा एक बस मार्शल्स को, एक सिविल डिफेंस वॉलियंटर को रिप्लेस कर सकता है? ये सबको पता है कि बिल्कुल नहीं कर सकता। आज यहां पे अनेकों सिविल डिफेंस वॉलिंटियर मौजूद हैं जिन्होंने बस मार्शल के तौर पे काम किया। मैं इन सबको सलाम करती हूँ कि पिछले नौ साल से लगातार ये दिल्ली की महिलाओं को सुरक्षा और सम्मान के साथ बस में सफर करने का मौका दे रहे हैं। इतने इन्सीडेंट्स हुए। एक बस में किसी एक बच्चे को किडनैप करने की कोशिश करी। वहां पे एक सिविल डिफेंस वॉलिंटियर बस मार्शल के तौर पे मौजूद था उसने देखा कि एक छोटी-सी बच्ची को घसीट के लेके जा रहे हैं उसने बस वहां रूकवाई और वो पीछे-पीछे भागता हुआ गया देखने के लिए कि वास्तविक तौर पे जो

व्यक्ति उस 4 साल की बच्ची को लेके जा रहे हैं वो उसके घर वाले हैं कि नहीं। उसने वहीं पर इंटरवीन किया, वहीं उसको रोका और इस चार साल की बच्ची को किडनैप होने से रोका। ये काम किया है सिविल डिफेंस वॉलिंटयर्स ने हमारी बसों में। जब महिलाओं के साथ अश्लील व्यवहार होता है, वहीं पर उस मौके पर वो बस को रोकते हैं उन अश्लील व्यवहार करने वालों को बस से बाहर करते हैं। इस बात को समझिए और मुझे लगता है कि ये बात सभी दिल्ली वालों को समझनी चाहिए कि इन सिविल डिफेंस वॉलिंटियर्स ने बस मार्शल बनके दिल्ली की महिलाओं को ना सिर्फ सुरक्षित सफर करने को मौका दिया, बल्कि सम्मान के साथ, अपने आत्मसम्मान को इंटैक्ट रखते हुए, अपनी डिग्निटी को इंटैक्ट रखते हुए सफर करने का मौका दिया। 2023 की जनवरी से बार-बार सवाल उठे कि जी ये बस मार्शल्स को रखना है कि नहीं, सीसीटीवी कैमरा काफी है, पैनिक बटन काफी है। तो मैं आपको बताना चाहूंगी और इस सदन के माध्यम से सभी दिल्लीवासियों को बताना चाहूंगी कि जब अलग-अलग विभाग के अफसरों ने ये सवाल उठाने शुरू किये तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल जी ने कहा कि हाँ मुझे पता है कि पैनिक बटन है, हाँ मुझे पता है कि सीसीटीवी कैमरा है, लेकिन अगर हम इस देश के प्रधानमंत्री को 12 लेयर सिक्योरिटी दे सकते हैं, अगर हम एक मुख्यमंत्री को 5 लेयर सिक्योरिटी दे सकते हैं तो क्या मैं अपनी बहनों को, अपनी बेटियों को तीन लेयर सिक्योरिटी नहीं दे सकता? हाँ मैं सीसीटीवी कैमरा लगवाऊंगा, हाँ मैं पैनिक बटन लगवाऊंगा और उसके साथ-साथ बस मार्शल्स भी

रखवाऊंगा कि हमारी दिल्ली की बेटियां, हमारी बहने बसों में सुरक्षित रहें। हमारे कैबिनेट साथी कैलाश जी उन्होंने आदेश दिया ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को कि बस मार्शल्स को कॉन्टीन्यू किया जायेगा। मैंने बतौर फाइनेंस मिनिस्टर आदेश दिया फाइनेंस डिपार्टमेंट को कि उनकी तनख्वाह को रिलीज किया जाये। बार-बार आदेश देने के बावजूद भी उनकी तनख्वाह को रिलीज नहीं किया गया और बार-बार ऑब्जेक्शन लगाये गए। 25 सितम्बर को कैलाश गहलोत जी ने सीसीटीवी और पैनिक बटन वाले मुद्दे पे बहुत क्लीयर कट डायरेक्सन दी कि पैनिक बटन होने के बावजूद, सीसीटीवी कैमरा होने के बावजूद ये सरकार का निर्णय है कि हम रखेंगे बस मार्शल। जितने पैसे की जरूरत हो महिलाओं को एक सुरक्षित सफर देने के लिए उसका प्रावधान दिल्ली सरकार करेगी, लेकिन ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर के आदेश के बावजूद, मेरे बतौर रेवेन्यु मिनिस्टर और फाइनेंस मिनिस्टर के आदेश के बावजूद, 31 अक्टूबर को रेवेन्यु डिपार्टमेंट ने आदेश दे दिये कि सभी सिविल डिफेंस वॉलिंटियर्स को हटा दिया जाए, उनको घर भेज दिया जाए। 31 अक्टूबर को ये ऑर्डर आया रेवेन्यु डिपार्टमेंट का। उसके तुरन्त बाद 1 नवम्बर को मैंने फिर से डायरेक्शन दी। मैंने कहा कि जो आपकी बाकी सिविल डिफेंस वॉलिंटियर पे ऑब्जेशन है उसपे हम बातचीत कर लेंगे, उसको हम लॉ डिपार्टमेंट को भेज देंगे, लेकिन बसों पे से मार्शल नहीं हटने चाहिए। ये महिलाओं की सेफ्टी को कॉम्प्रोमाइज करेगा, और मैंने रेवेन्यु डिपार्टमेंट को आदेश दिये कि आप अपने ऑर्डर को बदलिए और कम से कम बस मार्शल्स के तौर पे सिविल डिफेंस वॉलिंटियर्स को कान्टीन्यू करने दीजिए। मैं अध्यक्ष

महोदया बहुत दुख के साथ बताना चाहती हूँ कि दिल्ली सरकार के अफसरों ने दिल्ली की महिलाओं की सुरक्षा को ताक पे रखते हुए इस आदेश को नहीं माना। हमने एलजी साहब के पास भी फाइल भेजी। मुख्यमंत्री जी ने खुद एलजी साहब को लिखा कि कम से कम बस मार्शल्स के लिए तो आप सिविल डिफेंस वॉलिंटियर्स को कान्टीन्यू करने दीजिए हम बाकि सब मुद्दे पे बात कर लेंगे, लेकिन ये बहुत दुख की बात है कि एलजी साहब जो हमेशा कहते हैं मैं दिल्ली वालों की बहुत चिन्ता करता हूँ, वो इस बात के लिए नहीं माने और ये हजारों सिविल डिफेंस वॉलिंटियर्स जो सालों से दिल्ली की महिलाओं को सुरक्षा देते आये थे आज खुद सड़क पर पहुंच गए और बेरोजगार हो गए। अध्यक्ष महोदया, आप ये मत समझिए कि दिल्ली सरकार के अफसर खराब हैं, वो अफसर बहुत अच्छे हैं, वो ईमानदार हैं, वो काम करना चाहते हैं। ये वो ही अफसर हैं जिन्होंने इन सिविल डिफेंस वॉलिंटियर्स को रिकरूट किया। ये वो ही अफसर हैं जिन्होंने स्कीम को डिजाइन किया। ये वो ही अफसर हैं जिन्होंने अच्छे स्कूल बनाये, अच्छे मोहल्ला क्लीनिक बनाये, 24 घण्टे बिजली दी। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी और एलजी साहब इन अफसरों को डरा रहे हैं, इन अफसरों को धमका रहे हैं। मेरे साथी यहां पे बैठे हैं जो कैविनेट के मंत्री हैं। सब आपको बतायेंगे कि ये सब अफसर हमारे दफ्तर में आते हैं और उनकी आंखों से आंसू टपक रहे होते हैं। वो कहते हैं कि आज हमें डराया जा रहा है, हमें धमकाया जा रहा है कि अगर हमने केजरीवाल सरकार के साथ काम किया, आपके आदेशों का पालन किया तो हमारी नौकरी चली

जायेगी। हमें सस्पेंड कर दिया जायेगा। हम पर विजिलेंस इन्क्वायरी हो जायेगी। तो अध्यक्ष महोदया, ये जो सिविल डिफेंस वॉलिंटियर्स को निकाला गया है, ये जो बस मार्शल्स को निकाला गया है, इसमें अफसरों की भी गलती नहीं है इसके पीछे और शायद यही इनके भागने का कारण हैं। इसके पीछे भारतीय जनता पार्टी है और इनके एलजी साहब हैं जो अफसरों को डरा कर, अफसरों को धमका कर इस प्रकार के आदेश निकलवा रहे हैं। मैं आज भारतीय जनता पार्टी से ये पूछना चाहती हूँ कि आपको आम आदमी पार्टी से नफरत है, आपको हमसे नफरत है, आपको अरविंद केजरीवाल जी से नफरत है, लेकिन आपकी नफरत अब इतनी आगे पहुंच गई है कि आपको दिल्ली की महिलाओं से नफरत हो गई है। आपकी नफरत इतनी आगे पहुंच गई है कि इन हजारों लड़के, लड़कियों से आपको नफरत हो गई है जो दिल्ली की महिलाओं को सुरक्षा दे रहे थे। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को ये पता होना चाहिए कि ये एक लोकतंत्र है, ये जनता का शासन है। अगर आपको आम आदमी पार्टी की, अरविन्द केजरीवाल की नीतियां ठीक नहीं लगती हैं तो आप चुनावी मैदान में उतरिये ना। आम आदमी पार्टी को, अरविन्द केजरीवाल को चुनाव में हराइये। लेकिन इस प्रकार की घटिया राजनीति, इस प्रकार की गन्दी राजनीति कि आप अफसरों को डराकर, अफसरों को धमकाकर अरविन्द केजरीवाल के काम रोक रहे हैं, युवाओं की नौकरी छीन रहे हैं, महिलाओं की सुरक्षा छीन रहे हैं, इस प्रकार की गन्दी राजनीति भारतीय जनता पार्टी को बंद करनी चाहिए, ये मेरा भारतीय जनता पार्टी से आग्रह है। आज यहां पे बहुत

सारे सिविल डिफेंस वॉलिंटियर मौजूद हैं, बहुत सारे जो बस मार्शल्स के तौर पे काम करते थे वो भी मौजूद हैं। आज मैं दिल्ली सरकार की तरफ से, अरविन्द केजरीवाल जी की तरफ से आपको वादा कर रही हूँ कि जिस तरह से जब भी दिल्ली वालों पे कोई संकट आया है, दिल्ली वालों पर कोई परेशानी आई है, अरविन्द केजरीवाल जी एक कवच बनके, एक दीवार बनके सभी दिल्ली वालों के लिए खड़े रहे हैं। तो आज मैं इन सबको वादा कर रही हूँ सभी सिविल डिफेंस वॉलिंटियर्स और बस मार्शल्स से कि आप लोगों के हक की लड़ाई अरविन्द केजरीवाल की सरकार और आम आदमी पार्टी का एक-एक सिपाही सड़क से लेकर संसद तक लड़ेगा और जब तक सिविल डिफेंस वॉलिंटियर्स को वापस नहीं लगाया जाता है, हम इन लोगों की हक की लड़ाई लड़ते रहेंगे। बहुत-बहुत धन्यवाद अध्यक्ष महोदया।

माननीया अध्यक्षः माननीय मंत्री श्री सौरभ भारद्वाज जी।

माननीय स्वास्थ्य मंत्री (श्री सौरभ भारद्वाज): अध्यक्षा महोदया, ये मामला मेरे विभाग का नहीं है। आतिशी जी के विभाग का है इसलिए मैंने अपना नाम स्पीकर पे नहीं दिया हुआ था। मगर जब मैंने संजीव झा जी को सुना, मुझे लगा मुझे भी एक विधायक के तौर पे अपनी बात रखनी चाहिए। चूंकि मैंने इस विषय की तैयारी नहीं की, तो बहुत ज्यादा तकनीकी बात मुझे नहीं समझ में आई। मगर एक तकनीकी बात जो मुझे समझ में आई वो ये है कि अफसरों को ये कहा गया है कि आप फाईल पे कुछ भी उल-जुलूल लिखिए, कोई भी कुतर्क डालिए, सरकार की पॉलिसी को रोकिए और अफसरों को ऐसे कुतर्क

फाईल में लिखते हुए ना तो शर्म आती है, ना उन्हें इस चीज का अंदाजा होता है कि कल को आप फाईल पे अपनी कलम से जो बकवास लिख रहे हैं, उसके लिए आपको सजा हो सकती है, आप क्रिमिनल काम कर रहे हैं। भई आप अपनी प्रमिका को प्रेम पत्र नहीं लिख रहे जिसमें आप जो चाहे लिख दें। आप एक सरकारी फाइल पे अपने दस्तखत से एक आईएएस अफसर लिख रहा है और उसको भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आशिर्वाद मिला हुआ है कि तुम जो कुतर्क लिखना है लिखो इस फाइल पे, तुम्हारा कुछ होगा नहीं। वरना हिम्मत है किसी आईएएस अफसर कि वो फाइल पे लिख रहा है क्योंकि सीसीटीवी बसों में लग गए हैं तो आपको बस मार्शल्स की जरूरत नहीं है। ये तो कोरी बकवास है। भई सीसीटीवी तो आपके एलजी हाउस में भी बहुत सारे लगे हुए हैं, आप क्यों इतनी सिक्योरिटी लेकर घूम रहे हैं। छोड़िए आप अपनी सिक्योरिटी। मैं एलजी साहब को इस सदन की तरफ से एक मंत्री होने के नाते ये कह रहा हूँ, आपके यहां बहुत सारे सीसीटीवी लगे हैं, मैंने देखे हैं। और लगवाने हैं तो बता दीजिए आतिशी जी और लगवा देंगी, आप अपनी सिक्योरिटी छोड़ दीजिए। कब छोड़ेंगे बताइये, छोड़ेंगे? और जिस अफसर ने लिखा है इस फाइल पे वो अफसर भी एक पुलिस वाला लेकर घूमता है, मैंने खुद अपनी आखों से देखा है। वो क्यों लेके घूम रहा है? सीएस खुद अफसर लेके घूमते हैं, पुलिस के अफसर लेके घूम रहे हैं, क्यो घूम रहे हैं? वो भी छोड़ दें। भई जहां वो रहते हैं वहां भी सीसीटीव लगा हुआ है, जहां वो जिस सचिवालय में काम करते हैं वहां सीसीटीवी

लगा हुआ है। दिल्ली की हर सड़क पे सीसीटीवी लगा हुआ है आप भी अपनी सिक्योरिटी छोड़िये। ये कुतर्क कोई कैसे दे सकता है कि क्योंकि बस में सीसीटीवी लगा हुआ है तो बस मार्शल की जरूरत नहीं, मैं हैरान हूँ। सिर्फ और सिर्फ ये कुतर्क इस फाइल में नहीं दिये गए अध्यक्षा महोदय, हर फाइल में, चाहे वो हेल्थ डिपार्टमेंट की फाइल हो जहां पे डेटा एंट्री ऑपरेटर्स को निकाल दिया गया। ओपीडी के अंदर बेचारे गरीबों के बच्चे ओपीडी कार्ड बनाते थे एक फैसला किया गया सारे ओपीडी के जो बैठने वाले डेटा एंट्री ऑपरेटर हैं उन सबको निकाल दिया गया। एक फैसला दिया, जो 'फरिश्ते' स्कीम थी उसका पैसा सरकार की तरफ से रोक दिया गया। एक फैसला दिया जलबोर्ड की जितनी पेमेंट थी जितने ठेकेदारों की सारी पेमेंट रोक रखी है। जगह-जगह जो है सीवर की, पानी की परेशानी हो रही है। सारे फैसले अफसरों के कुतर्क द्वारा दिये जा रहे हैं और ये अफसर कुतर्क इसलिए दे रहे हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की शह है कि आप निहायत बकवास फाइल पे लिखें, कुतर्क लिखें, उन कुतर्कों के ऊपर हम सारे के सारे काम जो है दिल्ली सरकार के रोक देंगे। अब ये सिविल डिफेंस वॉलिंटियर बड़े भोले-भाले हैं। हालांकि इनको इतना भोला-भाला होने का हक नहीं है। ये इतने भोले-भाले हैं कि इनको अभी तक ये ही समझ में नहीं आया कि इनकी नौकरी कैसे गई। इनको गुमराह ही किया जा रहा है। भईया आप ये बात डिसाइड करिये, समझिए। जिन अफसरों ने आपको नौकरी से निकाला वो अफसर एलजी साहब के आंख के तारे हैं। ये मैं पूरे विश्वास से और पूरी अथोरिटी से कह रहा

हूँ, क्यों? जिस ट्रांसपोर्ट सेकेट्री ने इन गरीबों को निकाला, उस ट्रांसपोर्ट सेकेट्री को एलजी साहब ने अपना प्राइवेट सेकेट्री बना लिया, प्रिंसिपल सेकेट्री टू एलजी बना लिया सबके सामने। तो एलजी के आंख के तारे हुए ना। blue eyed boy हुए। दूसरे अफसर रेवेन्यु सेकेट्री हैं अश्वनी कुमार उनको भी एजली जो है अपने साथ रखते हैं। उनके बारे में कई शिकायतें हुई, उनको हटाने की कोई प्रक्रिया शुरू नहीं हुई। तो जो अफसर दिल्ली सरकार के कामों में रोड़ा अटका रहे हैं चाहे वो फाइनेंस सेकेट्री हों ए. सी. वर्मा जी, चाहे वो रेवेन्यु सेकेट्री हों अश्वनी कुमार, चाहे वो ट्रांसपोर्ट सेकेट्री हो आशीष कुन्द्रा, क्या एलजी साहब ने इनके खिलाफ कोई कार्यवाही की है, क्या केंद्र सरकार ने इनके खिलाफ कोई कार्यवाही की है कि तुमने 10 हजार बच्चे निकाल दिये तुम्हारे ऊपर ये कार्यवाही की जायेगी? अब संसद के चुनाव सातों सांसद भारतीय जनता पार्टी के हैं और उनके इलाकों में हजारों सिविल डिफेंस वॉलिंटियर हैं, क्यों नहीं जाते? आपको जाना चाहिए सांसदों के पास। अपने सांसदों को आप कहिए कि आप हमारे साथ एलजी साहब के घर चलिए और इन अफसरों को नौकरी से हटाइये। क्यों नहीं हटायेंगे एलजी साहब, हटायेंगे। भई या तो भारतीय जनता पार्टी के सांसद आपके साथ हैं या आपके खिलाफ हैं। अगर आपके साथ हैं तो लेके जाओ उनको एलजी साहब के घर और बोलो भई इन अफसरों को हटाया जाए। इन्होंने हमारे को नौकरी से हटाया और अगर वो सांसद आनाकानी कर रहे हैं, गोलमोल कर रहे हैं, जाने के लिए तैयार नहीं हैं, इसका मतलब एलजी साहब, भारतीय जनता पार्टी के सांसद और वो अफसर ये सारे मिले हुए हैं

और हमें जब कहो हम तब चलने के लिए तैयार हैं एलजी साहब के यहां। हम तो उससे आगे की बात करेंगे कि ना सिर्फ इनको निकाला जाये, इनके ऊपर मुकदमे चलाये जायें, इनको जेल में भेजा जाए। भई आप ऐसा कुतर्क लेके कैसे निकाल सकते हो हजारों बच्चों को? तो ये बात जो है सिविल डिफेंस वॉलिंटियर को अब समझनी पड़ेगी। इतना भोला-भाला रह के जो है देश में आप नहीं चला पाओगे। आप इसको तय करो। या तो भारतीय जनता पार्टी आपके साथ है या दिल्ली सरकार आपके साथ है और तय कराओ। ये गोलमोल-गोलमोल करने के चक्कर में सारे गेस्ट टीचर जो थे वो आउट हो गए। क्योंकि उनको समझ में ही नहीं आया कि उनके साथ कौन है और कौन उनके खिलाफ है। एलजी साहब उनको गोलमोल-गोलमोल करते रहे। हमने विधान सभा के अंदर कई बार रेज्यूलेशनपास किये उसके बावजूद जो है उनको नहीं रखा गया। ना उनको नम्बर दिये गए। इनको ये कहके बेवकूफ बनाया कि आप सबको होमगार्ड की तरह से जो है ले लेंगे और जब होमगार्ड की भर्ती निकाली है तो उसके अंदर जो है इनको कोई तरजीह नहीं दी गई है। मात्र मुझे लग रहा है छोटा-सा 5 नंबर इनको दे दिये गए। उससे इनका कुछ नहीं होगा। ज्यादातर ये जो सिविल डिफेंस वॉलिंटियर हैं इनकी उमर ज्यादा हो गई ये तो अप्लाई भी नहीं कर पायेंगे उसके अंदर। उसमें क्वालीफिकेशन डाल दी गई है। तो ये जो है सिर्फ और सिर्फ जो है सिविल डिफेंस वॉलिंटियर्स को गुमराह किया गया। इनको बेचारों को बेरोजगार किया गया और फिर इनको वहां पे धरने पे बिठा दिया गया, नहीं भई तुम तो सेक्रेटेरिएट के सामने बैठके धरना दो। और

वो बेचारे देते भी रहे बट उससे होगा क्या। जहां पे पावर है आपको उसके ऊपर जो है दवाब डालना पड़ेगा। ये आपने मुझे मौका दिया अध्यक्षा महोदया, मैं तैयारी से नहीं आया था बट मेरा बड़ा मन था कि मैं इस बात पे अपनी बात रखूं। आपने मुझे मौका दिया और आप बहुत अच्छी लग रही हैं आज इस कुर्सी पे आपको बहुत-बहुत बधाई।

माननीया अध्यक्षः बहुत-बहुत धन्यवाद। अब सदन की कार्यवाही वीरवार दिनांक 29 फरवरी,

श्री राजेन्द्र पाल गौतमः माननीय अध्यक्षा जी मैं इसपे एक रेज्यूलेशन लाना चाहता हूँ जो बहाना बनाकर वो गए हैं, वो सदन में वो रेज्यूलेशन आये। उसपे पास हो चूंकि पहले इसपे मैं चर्चा कर चुका हूँ और माननीय स्पीकर साहब ने कहा था आप रेज्यूलेशन लाइये, उसको सदन में पास किया जायेगा ताकि हम, जो विपक्ष है, जो बहाना बना रहा है टालने का वो टालने के बहाना से बच सके। मैंने ऑलरेडी एप्लीकेशन भी लगा दी है तो आप परमिशन दे ताकि उसको रेज्यूलेशन को लाया जा सके।

माननीया अध्यक्षः आपने लिखित में दिया।

श्री राजेन्द्र पाल गौतमः हाँ लिखित में मैं दे चुका हूं।

माननीया अध्यक्षः आपके विषय को कल संज्ञान में ले लिया जायेगा। अब सदन की कार्यवाही वीरवार दिनांक 29 फरवरी, 2024 को

पूर्वाह्न 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। सभी विधायक साथी लंच के लिए आमंत्रित हैं। धन्यवाद।

(सदन की कार्यवाही वीरवार दिनांक 29 फरवरी, 2024 को पूर्वाह्न 11 बजे तक के लिए स्थगित की गई।)

© दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र शासन अधिनियम, 1991 की धारा 18 (2) के उपबंधों तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली विधान सभा प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 281 (2) के प्रावधानों के अंतर्गत प्रकाशित तथा ग्राफिक प्रिंटर्स, 2965 /41, बीडनपुरा, करोल बाग, नई दिल्ली-110 005 द्वारा मुद्रित।